नवम्बर 2021

₹15

मीडिया मंच

www.mediamanch.in

सम्पूर्ण समाचार पत्रिका

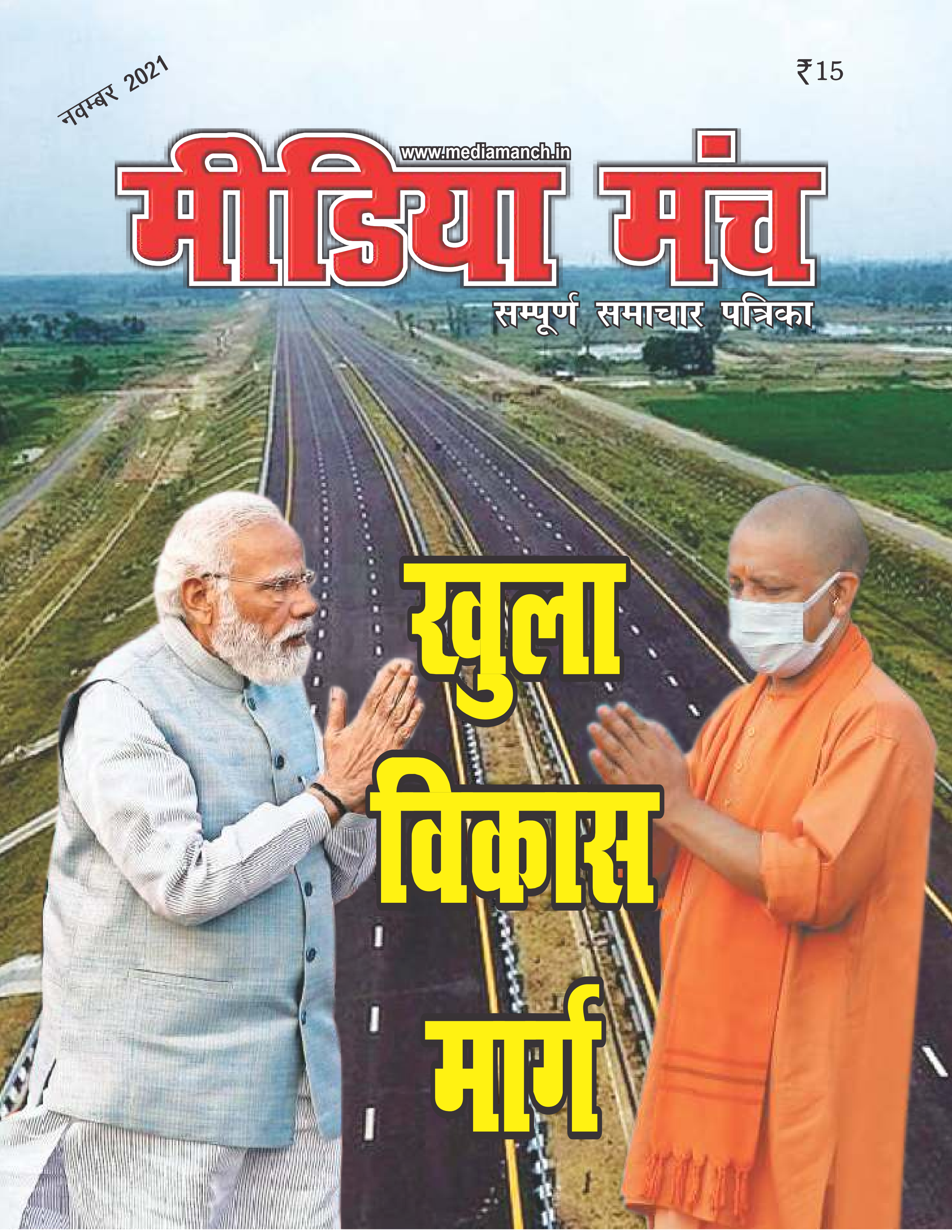

खुला विकास मार्ग

किसे चोट पहुँचायेगा जिन्ना का जिन्न

1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई

सोच ईमानदार, काम दमदार

मीडिया मंच

वर्ष – 24

अंक – 07

संपादक

तेज बहादुर सिंह

सलाहकार संपादक

हनुमान सिंह 'सुधाकर'

कार्यकारी संपादक

वीरेन्द्र शुक्ल

समाचार संपादक

वीरेन्द्र सिंह

वरिष्ठ फोटोग्राफर

योगी, अजय सिंह इंद्रेश रस्तोगी

मार्केटिंग

सिग्मा ट्रेड विंग्स

लेआउट

विष्णु बिसेन

स्वात्वाधिकारी 'मीडिया मंच पब्लिकेशन्स' के लिए प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक टी.बी. सिंह द्वारा प्रिंट आर्ट, कैन्ट रोड, लखनऊ से मुद्रित तथा जी–7, खुशनुमा कॉम्पलेक्स, 7–मीराबाई मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

RNI No. : UPHIN/1998/5628

समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा

वेबसाइट :
www.mediamanch.in

ई-मेल :
mediamanch@ymail.com
tejsingh007@yahoo.com

मोबाइल–09415000151

जिन्ना का.... 13

स्थायी स्तम्भ

अतिथि	05
ब्यूरोक्रेसी	34
स्वास्थ्य	39
खेल	41
आंखिन देखी	43
फिल्म	47
यूपीनामा	48

टी.बी. सिंह

संपादकीय

सिर उठाता उग्रवाद

असम राइफल्स की एक यूनिट ने जिस तरह कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ ही उनकी पत्नी और बेटे सहित पांच जवानों की जिस तरह से घात लगाकर हमला करते हुए जान ले ली, वह बेहद दुःखद और निंदनीय है। लेकिन जिस दिन मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में उग्रवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया उसी के आसपास बिहार जिले के गया में एक गांव में भी नक्सलियों ने उत्पात मचाते हुए 4 ग्रामीणों की न केवल हत्या कर दी बल्कि शक के चलते जघन्य हत्या करने के बाद दो घरों को बमों से उड़ाकर दहशत और अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश की। यही नहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में दो दर्जन से अधिक नक्सलियों का पुलिस के निशाने पर आना यह दर्शाता है कि उग्रवाद पर अंकुश के लिए अभी बहुत कारगर और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। मणिपुर की बात करें तो कर्नल विप्लव विगत जुलाई में ही मिजोरम से मणिपुर आए थे। उन्होंने बहुत जल्द ही अपने काम से एक अलग पहचान बना ली थी। उग्रवादियों पर वह निरंतर आक्रामक थे। केवल उग्रवाद पर शिकंजा कसने को लेकर ही वह उग्रवादियों के निशाने पर थे बल्कि हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने वालों पर भी वह निरंतर शिकंजा कसते चले जा रहे थे। उनके इस तेजतर्रार कार्रवाईयों से वह उग्रवादियों और तस्करों के निशाने पर आ गए थे। यह घटना जिस थिंगाट के पास हुई वह उस चंदेल से 50 किमी दूर है जहां सन 2015 में एनएससीएन (खपलांग गुट) और उल्फा के उग्रवादियों के हमले में 20 सैनिकों की जान चली गई थी। इसके बाद सुरक्षाबलों की तत्काल हुई आक्रामक कार्रवाई से उग्रवादी घटनाओं में कमी आई। जिससे मणिपुर में उग्रवादी संगठनों के कमजोर पड़ने की बात कही जाने लगी थी। लेकिन भले ही पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन मणिपुर अभी भी उग्रवाद का गढ़ बना हुआ है। इस समय 20 से अधिक उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं। मणिपुर में तो पीएलए सहित आधा दर्जन से ज्यादा गुट अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जहां देशी उग्रवादियों की गतिविधियां चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें उकसाने में पड़ोसी चीन की भी भूमिका देखने को मिल रही है।

कई उग्रवादी संगठन चीन की मदद से नए सिरे से उग्रवाद को बढ़ावा देने की मंशा पाले हुए हैं। म्यामार में कई उग्रवादी गुटों के कैंप हैं जो पूर्वोत्तर में हिंसा की साजिश रचते हैं। इनका चीन से मजबूत कनेक्शन है। मणिपुर में तो पीएलए का चीन से मजबूत रिश्ता है। इसके अलावा कई अन्य गुट भी चीनी सेना के संपर्क में बताए जाते हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम- इंडिपेंडेंट के प्रमुख ने म्यामार की सीमा से सटे दक्षिणी चीन के रूईली में नया ठिकाना बनाया था। पिछले साल अरूणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के जवानों की हत्या के बाद भी इस तरह की आशंकाएं लगने लगी थीं कि चीन सीमा विवाद के साथ-साथ पूर्वोत्तर में नया मोर्चा खोलने की फिराक में है। यह आम बात हो चली है कि चीनी सेना पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादी संगठनों को शह देने में संलिप्त है। उग्रवादी पूर्वोत्तर में हिंसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे कारण यह है कि वे वहां अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। इसी के चलते जब 1975 में भारत सरकार और नगा नेशनल काउंसिल के बीच सिलांग समझौते का एसएसखापलांग व थिंगालेंग शिवा जैसे नेताओं ने विरोध किया था। उस समय वे 'चाईना रिटर्न गैंग' कहलाते थे। इसके अलावा और भी कई उग्रवादी संगठन यहां पनपते रहे। जैसे 1980 में खापलांग व मुईवा ने नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नगालिम का गठन किया था। 1998 में ईसाक मोईवा ने चिशीश्वुसंग एनएससीएन (आई-एम) गुट का गठन कर डाला था। जबकि खापलांग ने अपने गुट को एनएससीएन (के) नाम दिया। मणिपुर में अगस्त 2021 तक गृहमंत्रालय ने सक्रिय आठ विद्रोही समूहों को सूचीबद्ध किया था। उक्त आतंकी हमले के बाद पूर्वोत्तर में उग्रवादी गुटों की चुनौती को लेकर एजेंसियां एक बार फिर 'हाईअलर्ट' पर हैं। साथ ही सुरक्षा एजेसिंयां उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहीं हैं। उग्रवाद का दूसरा रूप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में देखने में आया जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मारे गए नक्सलियों पर 1.36 करोड़ का ईनाम था। ❑

पत्रकार हितों के लिए कृत संकल्प : मौर्य

प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आईएफडब्ल्यूजे (इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट) के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि योगी सरकार पत्रकारों के हितों के लिए कृत संकल्प है।

श्रम मंत्री ने पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में यह सहमति भी जताई की देश के अन्य राज्यों में श्रमजीवी पत्रकारों को मिल रही पेंशन की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में भी अविलंब लागू करने की जरूरत है। वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की तरह यूपी के पत्रकारों को भी पेंशन मिलनी चाहिए और मैं उनकी मांग से सहमत हूं।

आईएफडब्ल्यूजे से संबद्ध यूपीडब्ल्यूजेयू के प्रतिनिधि मंडल में यूपीडब्ल्यूजेयू अध्यक्ष टी.बी. सिंह, सचिव राजेश मिश्रा, संगठन सचिव अजय द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर व आशीष बाजपेयी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने श्रम मंत्री को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इसके आलावा प्रतिनिधि मंडल में आईएफडब्ल्यूजे के प्रधान महासचिव परमानंद पांडेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मान्यता प्राप्त संवाद दाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी व आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस भी शामिल थे।

इस अवसर पर हेमंत तिवारी ने श्रम मंत्री को ज्ञापन में उल्लिखित मांगों की जानकारी देते हुए कहा कि पत्रकारों का पेंशन संबंधी प्रतिवेदन सरकार के पास लंबित है और इसका परीक्षण भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी के आसपास के सभी राज्यों मसलन उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पत्रकार पेंशन से वंचित हैं। श्रम मंत्री से परमानंद पाण्डेय ने श्रम न्यायालयों को और भी प्रभावी बनाने व पत्रकारों के सेवा योजना संबंधी मामलों को समय बद्ध तरीके से निपटाने की बात की। टी.बी. सिंह ने कहा कि कोरोना काल में अखबारों ने आर्थिक कारणों का हवाला देकर और मजीठिया वेतन मान मांगने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्रम विभाग को उनकी बहाली के लिए कदम उठाना चाहिए।

श्रम मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि वह स्वयं पेंशन के संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों की छंटनी के संबंधी जो मामले उनके संज्ञान में आए हैं उनमें उन्होंने मदद का आदेश दे रखा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि श्रम न्यायालयों को और भी प्रभावी बनाया जाएगा।

पैरा पदकवीरों का सम्मान

पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को न केवल प्रोत्साहन और सुविधा ही मिल रही है बल्कि उन्हें सम्मानित भी जोरदार ढंग से किया जा रहा है।

मेरठ में टोक्यो पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान देने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक विशेष खेल समारोह में भी ओलंपिक पदक वीरों पर जमकर धनवर्षा की थी।

सिटी ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में पहचान रखने वाले मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ टोक्यो पैरालंपिक के 17 पदक विजेताओं और प्रदेश के 6 टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप कुल 32.5 करोड़ की धनराशि का चेक, मोमेन्टो और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी घोषणा की कि पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को भी 10-10 लाख की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बीच शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है यह अभिनंदनीय है। खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और हमारी पहचान है देश। भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान हमारा नैतिक दायित्व है।

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय परिसर में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में खेल और खिलाड़ियों के लिए खूब किया, भविष्य में और भी नया करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेरठ में बनने वाले प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के बारे में कहा कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेश के साथ ही देश के खेल और खिलाड़ियों का विकास होगा उन्हें नया आयाम मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सांसद खेल प्रतियोगिताएं हो रहीं हैं। इसका सकारात्मक और बड़ा असर जरूर दिखेगा।

समारोह में उपस्थित केन्द्रीय खेल एवं युवा कल्याण तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेरठ के खेल और खेल उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में यह खेल नगरी और बड़ी उपलब्धियों हासिल करेंगी।

सुहास को मुख्यमंत्री ने सराहा

टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले सुहास एल. वाई. को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने न केवल चार करोड़ रुपये का चेक सौंपकर न केवल सम्मानित ही किया बल्कि उन्होंने नोएडा के डीएम सुहास एल.वाई. की प्रशंसा भी की। केवल यही नहीं मुख्यमंत्री ने सुहास को पांच विशेष वेतन वृद्धि देने का एलान भी किया।

मेरठ में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा के डीएम ने देश को न केवल मेडल ही दिलाया है बल्कि उन्होंने कोरोना काल में सराहनीय कार्य भी किया है। योगी ने कहा कि जब नोएडा कोरोना से जूझ रहा था जब सुहास लोगों को बचाने के लिए शानदार काम कर रहे थे। कोरोना संकट के समय पैरालंपियन दिव्यांगता को पीछे छोड़कर देश के लिए लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश से टोक्यो पैरालंपिक में केवल सुहास एल.वाई. ने ही न केवल पदकीय प्रदर्शन किया बल्कि नोएडा के ही एथलीट प्रवीण कुमार ने भी रजत पदक जीतने के फलस्वरूप चार करोड़ की धनराशि सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खिलाड़ियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित कर उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन नहीं देने की धारणा को बदल दिया है। खिलाड़ियों के सम्मान से यूपी की तस्वीर बदलेगी।

काम से मिलती है पहचान

दूरदर्शितापूर्ण सोच और कार्य से मिली सफलता : अरूण

• वीरेन्द्र शुक्ल

बिंदास मिजाज और अंदाज के डा. अरूण कुमार सिंह के कार्य भी बिन्दास रहते आए हैं। अपने काम से अपनी छाप छोड़ने और पहचान बनाने वाले अरूण सिंह ने लोगों को नई राह दिखाई है।

वैसे वह अभी युवा ही हैं लेकिन उन्होंने कम अनुभव रखने के बावजूद नई सोच, लगन और उत्साह से कई ऐसे काम कर डाले हैं जो अनुभवी और पुराने प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाए हैं।

वह अभी तक दो ही तीन तहसीलों में रहे पर लखीमपुर खीरी में एसडीएम के पद पर रहते हुए उन्होंने काम के मामले में नए कीर्तिमान गढ़ डाले हैं। लखीमपुर में लगभग साढ़े तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने एक नहीं बल्कि दो आईएसओ प्रमाण पत्र हासिल किए, वह और लोगों के लिए नजीर के रूप में सामने है। संभवतः वह ऐसे पहले तेजस अधिकारी हैं जिन्होंने एक ही तहसील में रहते हुए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने का गौरव हासिल किया है। उनकी यह उपलब्धि न केवल बेमिसाल है, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक कार्य करने वाले पहले पीसीएस अधिकारी हैं। लखीमपुर खीरी के सदर तहसील में पहले तो उन्होंने आईएसओ 9001 और फिर आईएसओ 14001 प्रमाण पत्र हासिल कर अपने को कर्मठ और कर्तव्यशील अधिकारी के रूप में स्थापित कर रखा है। केवल यही नहीं जब वह इससे पहले कन्नौज में थे तब भी उन्होंने एक चर्चित और क्रांतिकारी काम किया।

अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान एसडीएम सदर कन्नौज में रहते हुए उन्होंने ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन का उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कन्नौज में राजा जयचंद के विशाल महल आदि को मोहम्मद गोरी ने धोखे से आक्रमण कर कन्नौज नगर को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन 1194 ईसवी में ध्वस्त और अब खंडहर के रूप में जयचंद के अव्यवस्थित टीले की उन्होंने अन्य अफसरों की तरह अनदेखी नहीं की बल्कि अव्यवस्थित और बिखरे पड़े पुरातात्विक महत्व के स्थलों और सामानों के

संरक्षण के लिए अभियान छेड़ा। ग्रामीणों के मदद से उन्होंने गंगा किनारे स्थित टीले और गुम्बदों को देखकर जानकारी जुटाने के लिए पगडंडियों पर अपनी टीम के साथ खोजबीन करने के लिए निकल पड़े। कानपुर और कन्नौज जिले की सीमा पर गंगा किनारे बसे दाईपुर गांव के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पुरातन संपदाओं की खोज के लिए प्राचीन स्थलों को चिन्हित कर उनकी नाप जोख कराई। अपनी टीम के साथ पगडंडियों की खाक छानते हुए उन्होंने प्राचीन धरोहरों और ऐतिहासिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए तन मन से जुट गए। संरक्षण के साथ-साथ उन्होंने अवैध अतिक्रमण को भी हटवाने का काम किया। उनके प्रयासों से प्राचीन संपदा और उसके इर्दगिर्द संरक्षित जगहों पर कब्जा करने वाले को चिन्हित कर कब्जेदारों को ध्वस्तीकरण की नोटिस देकर पुरातन संपदा पर कब्जा जमाकर भवन निर्माण करने वाले भू माफियाओं की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने उन बिखरी पड़ी मूर्तियों और सिक्कों आदि को सहेज कर संग्रहालय में भेजा।

इसी तरह तिरवा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि विवाद निपटाने के लिए एलडीएफ जैसी नई परिकल्पना को साकार किया। एलडीएफ यानी 'लैंड डिस्प्यूट फ्री' जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे उन्होंने सरकारी भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू माफियाओं द्वारा कब्जाए गए हजारों एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसके चलते जहां उन्होंने अपने इस एलडीएफ कांसेप्ट से पीड़ित लोगों को भारी राहत पहुंचाया तो वहीं उन्होंने मोरंग की अवैध मंडी को खत्म करने का भी साहसिक कार्य किया। तिरवा में मोरंग की अवैध मंडी लगती थी। इस गैर कानूनी कार्य को समाप्त करने की मंशा से उन्होंने एक दिन मात्र दो होम गार्डों की मदद से 54 ट्रकों को पकड़ा। इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच जाना स्वाभाविक था। उनके इस साहसिक पहल के चलते अवैध खनन से लायी गई मोरंग व गिट्टी की लगने वाली मंडी बंद हो गई। इस दौरान उन्होंने अपने जान की परवाह भी नहीं की। जबकि उन्हें कई तरह की धमकियां मिलती रहीं। पर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे।

इन तमाम उल्लेखनीय कार्यों के उपरान्त जैसे उनके द्वारा अभी और काम किया जाना बाकी था। मार्च 2018 में लखीमपुर आने के बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक काम को अंजाम दे डाला और जनता के बीच लोकप्रियता का शीर्षग्राफ छू डाला। यहां उन्होंने ढेरों ऐसे काम किए जिसकी चर्चा उनके वहां न रहने के बावजूद आज भी होती रहती है।

हमेशा लीक से हटकर काम करने में यकीन रखने वाले अरूण सिंह के दूर दर्शिता पूर्ण सोच और कार्य के चलते लखीमपुर के एसडीएम सदर अरूण सिंह ने पहले आईएसओ 9001 का प्रमाण पत्र पाया तो फिर आईएसओ 14001 का भी तमगा अपने नाम किया।

गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए उन्हें आईएसओ 9001 का प्रमाण पत्र मिला। उन्होंने लखीमपुर सदर की रंगत ही बदल डाली। उनके विशेष प्रयासों के चलते इस तहसील ने यदि आईएसओ 9001 का प्रमाण पत्र हासिल किया तो यह जायज भी था। वैसे तो प्रदेश में आईएसओ प्रमाणित और भी तहसीलें हैं लेकिन मल्टीनेशनल तर्ज पर कारपोरेट कल्चर की आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाली इस तहसील को उन्होंने यूपी की पहली तहसील बनाया।

इस संदर्भ में अरूण सिंह का कहना है कि जब वह अपनी तहसील में आने वाले फरियादियों की दशा और दुर्दशा देखते थे तो उन्हें अत्यंत पीड़ा होती थी। उनका मानना है कि तहसील और थानों में आने वाला व्यक्ति किसी न किसी तरह पीड़ित ही होता है। ऐसे में उसकी परेशानियों और अज्ञानता का लाभ तहसीलों में मौजूद दलाल सक्रिय रहते हैं। इसके चलते तहसील दलाली का अड्डा बन जाती है। तहसील को इसी दलाली से मुक्ति दिलाने और आम जन में तहसील को लेकर

तालाब खोजो, तालाब बचाओ अभियान

लखीमपुर खीरी में रहते हुए अरूण कुमार सिंह ने एक और बड़ा नेक और उल्लेखनीय कार्य 'तालाब खोजो, तालाब बचाओ' अभियान के रूप में किया। उप जिलाधिकारी सदर रहते हुए उन्होंने इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण व भूगर्भ जल के संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत सराहनीय कार्य किया जो अंततः मील का पत्थर साबित हुआ। उन्हीं के विशेष प्रयासों और लोगों के सहयोग से इस इलाके में पहचान खो चुके तालाब, पोखर, सरोवर व नदियां पुनः अस्तित्व में आईं।

उन्होंने देखा कि तराई का यह इलाका पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां वन हैं, जंगल हैं तमाम तालाब, नदियां, पोखरे आदि सब कुछ हैं। लेकिन अतिक्रमण के चलते पर्यावरण को ढेरों नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने विस्तृत कार्य योजना

बनाई और संबंधित विभागों मसलन नगर पालिका व चकबंदी विभाग के लोगों के साथ नियमित बैठक कर भावी योजनाएं बनाईं।

तालाब खोजो अभियान के अंतर्गत उन्होंने तीन काम किए। उन्होंने विलुप्त हो चुके तालाबों की खोज के लिए अभिलेखों में कागजों में तालाबों की खोज शुरू करवाई। उन्होंने पाया कि इलाके में पांच हजार तालाबों का विस्तृत जाल फैला हुआ है। लेकिन अब अधिकांश खोजबीन करने पर नहीं मिले। लोगों ने तालाबों को पाटकर फर्जी इंट्री या पट्टे करवा लिए थे। इसके लिए उन्होंने कार्रवाई करते हुए उन विलुप्त तालाबों को तालाब के खाते में दर्ज करवाया। मौके पर पहुंचकर सब कुछ चिन्हित भी कर दिया।

इसी तरह तालाब बचाओ अभियान के तहत उनके द्वारा दो चीजें हुईं। पहली अतिक्रमण की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई ही न केवल की गई बल्कि जिन्होंने तालाब को पाट दिया था या पाट रहे थे उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई साथ ही उन्हें पकड़कर उन्हीं के माध्यम से तालाब बनवाने का कार्य करते थे। इसके तहत राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होती गई। दोषी व्यक्ति के विरूद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। जो दूसरा कार्य था वह तालाबों को मुक्त करना था। जो तालाब नष्ट हो गए थे उन्हें विकास विभाग के सहयोग से मूल स्वरूप में लाने का काम उन्होंने करवाया था। इसमें मनरेगा के माध्यम से काम हुआ। जिससे प्रवासी मजदूरों को जीविका मिलने में आसानी हो गई। इस तरह तालाबों का पुनरोद्धार करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह का नायाब काम करने के चलते उन्हें आईएसओ 14001 का प्रमाण पत्र हासिल हुआ। यह प्रमाण पत्र उन्हें फरवरी 2020 में मिला। इस शानदार उपलब्धि और बेहतरीन कार्य करने के लिए कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने लखीमपुर पहुंचकर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। आईएसओ 2014 का प्रमाण पत्र किसी संगठन द्वारा व्यवस्थित रूप से अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रबंधन के लिए उपयोग करने के लिए दिया जाता है।

आईएसओ 9001 मिलने के बाद अपने निर्धारित लक्ष्य आईएसओ 14001 को तहसील लखीमपुर सदर द्वारा अरूण सिंह के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सका। इस दौरान कमिश्नर ने तहसील का निरीक्षण करते हुए तहसील प्रशासन की प्रसंशा की और साथ ही जल संरक्षण को लेकर उनके द्वारा चलाए गए तालाब खोजो, तालाब बचाओ अभियान की भरपूर प्रसंशा भी की। आईएसओ 14001 में ध्येय पानी, बिजली तथा कागज की खपत कम करना है। जिसके लिए तहसील परिवार ने पानी की खपत का लक्ष्य निर्धारित करके पानी के पुर्नचक्रण व वर्षा जल के संचयन प्रणाली को अपनाया। बिजली की खपत कम करने के लिए एलईबी व बीईई स्टार रेटिंग वाले उपकरणों के उपयोग पर बल दिया गया। कागज की बचत के लिए आंकड़ों, दस्तावेजों व पत्रावलियों को डिजिटिलाइज किया गया। साथ ही ध्वनि व वायु प्रदूषण कम करने के लिए साईलेंट जनरेटर का उपयोग किया गया। जन जागरूकता के लिए तहसील परिसर में साईनेज लगवाए गए और परिसर में खाली पड़े स्थान पर फल व छायादार वृक्षों को रोपित किया गया।

इन सब का श्रेय अरूण कुमार सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ सेवक के रूप में खुद ने लेते हुए इन तमाम विशिष्ट उपलब्धियों का श्रेय अपने वरिष्ठों को देते हैं। उनका कहना है कि उस वक्त के डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह और सीडीओ अरविंद सिंह के मार्गदर्शन के साथ ही कनिष्ठों के सहयोग के चलते वह इतनी ऊँचाईयां हासिल करने में सफल हो सके।

बनी गलत धारणा को दूर करने के लिए ही उन्होंने कुछ नया करने की सोची ताकि यहां आने वाला पीड़ित शख्स अपना दुःख दर्द भूल सके। इस बदलाव की सोच के जनक तो अरूण सिंह ही थे लेकिन इसका श्रेय वह अपने तहसील स्टाफ को देते हैं। जिसकी वजह से उनकी तहसील किसी मल्टीनेशनल कंपनी के दफ्तर से अब कम नजर नहीं आती है। अपनी तहसील को कारपोरेट आफिस शरीखा बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके लिए उन्होंने लेखपाल सहित तमाम कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड की व्यवस्था की। तहसील को मल्टीनेशनल कंपनी का लुक देने के लिए जहां अरूण सिंह की मेहनत रंग लाई वहीं उनके स्टाफ का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला और आम लोगों की सहभागिता भी बेहद रही। इस तहसील को नया लुक देने में लगे खर्च का वहन राजस्व परिषद ने यद्यपि किया लेकिन उन्हें निर्माण कार्य में भरपूर जन सहयोग भी मिला। लोगों ने उनके इस अनोखे अभियान में बढ चढ़कर हिस्सा लेते हुए श्रम कार्य और निर्माण सामग्री आदि के लिए धन भी उपलब्ध कराया।

तहसील के कारपोरेट आफिस के रूप में तब्दील होने में 6 महीने का वक्त लग गया। अब उनकी तहसील कोई खंडहर जैसे सरकारी दफ्तर के रूप में नहीं बल्कि एक कारपोरेट आफिस के रूप में दिखने लगी थी। केवल बिल्डिंग तक ही नयापन

नहीं था बल्कि तहसील के इस नए बिल्डिंग में फरियादियों के लिए उनकी सुविधा के लिए एक बोर्ड भी लगाया गया। तहसील का सभागार अब किसी मल्टीनेशनल आफिस के मीटिंग हाल से कम नजर नहीं आने लगा था। तहसील में आने वाले आगंतुकों के लिए उनकी जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए उनके बैठने की समुचित व्यवस्था की गई। शौचालयों को माडर्न व स्वच्छ बनाया गया। स्वच्छता को ध्यान में रखकर जगह-जगह कूड़े दान की व्यवस्था की गई। महिला फरियादियों की सुविधा के लिए अलग से टायलेट की भी व्यवस्था की गई थी।

आईएसओ पमाण पत्र देने से पहले आईएसओ की टीम ने लगातार तीन दिनों तक तहसील में मिलने वाली सुविधाओं को जांचा-परखा। यही नहीं तहसील में साफ-सफाई व लोक सभागार सहित लेखपाल व कानून गो के केबिनों को सराहा। साथ ही ड्रेस कोड सहित अन्य सब कुछ व्यवस्थित देख आईएसओ की टीम ने लखीमपुर तहसील को आईएसओ 9001 का दर्जा दिया।

यह प्रमाण पत्र प्रशासन द्वारा गुणवत्ता परक सेवाएं देने के लिए ही आईएसओ ने प्रमाण पत्र दिया था। क्योंकि यहां जन मानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होने लगा था। जन कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करके बिचौलियों और दलालों की भागीदारी बंद कर दी गई थी। तहसील की संपत्ति का नामांकन करके उसका रख-रखाव सुनिश्चित कर दिया गया था। राजस्व कर्मी व काश्तकारों के बैठने व पेयजल की उचित व्यवस्था कर दी गई थी साथ ही वाहन पार्किंग व राजस्व अभिलेखों की रख-रखाव की समुचित व्यवस्था से युक्त गुणवत्तापूर्ण ढंग से तहसील का कायाकल्प आईएसओ टीम को बहुत भाया।

अरुण सिंह के अनुसार गुणवत्तापरक कार्यशैली के लिए आईएसओ द्वारा तहसील के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की क्वालिटी मैनेजमेंट की परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें तहसील के कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों ने उक्त परीक्षा में सफलता हासिल की। आईएसओ टीम का निर्देशन कर रहे धनंजय मिश्रा के निर्देशन में सफल लोगों द्वारा तहसील का परीक्षण किया गया। आईएसओ की सदस्य टीम में के.के. गोगिया, अल्ताफ, रमाकांत दीक्षित शामिल थे।

जहां तक डा. अरूण कुमार सिंह की बात है तो उनका जन्म मऊ जिले के ग्राम दिघेड़ा, परसुपर में हुआ। प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई जबकि इण्टर उन्होंने मऊ से किया। उच्च शिक्षा के लिए वह इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद दर्शनशास्त्र में एम.ए. किया। जूनियर फेलोशिप के तहत रिसर्च स्कालर के रूप में उन्होंने पढ़ाने का कार्य भी किया। फिर पी.एच.डी., डिफिल 2009 में पूरी हुई। पी.एच.डी. का उनका विषय निरश्वरवादी अस्तित्वाद में मानवीय मूल्य थी। अध्यापन से जुड़े रहने के बावजूद वह समाज के लिए कुछ और करना चाहते थे। जिस प्लेटफार्म की उन्हें तलाश थी वह उन्हें पीसीएस बनने में दिखी। फिर उन्होंने देश, दुनिया, समाज के लिए कुछ करने की ललक के चलते पीसीएस का इम्तिहान 2013 में दिया जबकि उन्हें बैच 2015 का मिला।

फिलवक्त वह राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण में ओएसडी के रूप में कार्यरत हैं। एलडीए में उन्होंने ज्वाइनिंग विगत 26 अक्टूबर 2021 को दी। ❑

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास 20 अकबर रोड पर हुई आत्मीय मुलाकात। श्री बिरला ने पत्रिका 'मीडिया मंच' को विस्तार से देखा और प्रकाशित सामग्री के बारे में जानकारी हासिल की और सराहा भी।

खुला विकास मार्ग

वीरेन्द्र सिंह
9410704385

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरब के विकास मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लड़ाकू विमानों ने एयर शो भी किया। सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एण्ड गो ऑपरेशन के तहत करतब दिखाए। प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के विकास का नया मार्ग खोलेगा। इस अवसर पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया।

मोदी ने कहा कि 340 किमी एक्सप्रेस वे की विशेषता यह है कि यह एक्सप्रेस वे अभी तक उपेक्षित रहे उन शहरों को लखनऊ से जोड़ेगा जिनमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों को इसका फायदा मिलेगा। यूपी सरकार ने आज भले ही इस पर 22 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च किए हों, लेकिन आने वाले समय में यह एक्सप्रेस वे लाखों करोड़ों के उद्योगों को यहां लाने का जरिया बनेगा।

लाखों उद्योगों का खुलेगा मार्ग

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश का विकास तभी संभव है जब संतुलित विकास हो। सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास जरूरी है। समान रूप से विकास तभी हो सकता है जब कनेक्टिविटी हो। आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है वे सब पूरे प्रदेश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ेंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इन शहरों में उद्योग की संभावना बढ़ेगी।

विकास का सपना हो रहा साकार

पीएम मोदी ने कहा कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी। कानून व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं थी। मेडिकल सुविधाओं की स्थिति से भी आप लोग अवगत है। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं बल्कि गांव-गांव नई राह बन रही है। नई सड़के बन रहीं हैं। बीते साढ़े चार साल में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। यूपी सरकार की सक्रिय भागीदारी से अब विकास का सपना साकार हो रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में नए मेडिकल कालेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे का लाभ गरीब को भी होगा और

मध्यम वर्ग को भी, किसान को इसकी मदद मिलेगी और व्यापारी के लिए सुविधा होगी। श्रमिक, उद्यमी को भी इसका लाभ मिलेगा। दलित, युवा, पिछड़े, किसान, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसे विशाल प्रदेश में एक शहर दूसरे शहर से काफी कटा हुआ था। अलग-अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे लेकिन एक दूसरे शहरों में कनेक्टिविटी न होने से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना कठिन होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए परिवार तक ही विकास सीमित था, लेकिन आज जितना पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए प्राथमिकता है। यह एक्सप्रेस वे आज यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इसके बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ-साथ बिहार के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली से बिहार आना-जाना और आसान हो जाएगा।

पहले परिवारवादियो का कब्जा था

पीएम मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति घर भी बनाता है तो पहले रास्तों की चिंता करता है, मिट्टी की जांच करता है, दूसरे पहलुओं पर विचार करता है, लेकिन यूपी में हमने ऐसी सरकारों का दौर देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही बड़े-बड़े सपने दिखाए। परिणाम यह हुआ कि यहां कारखानों में ताले लग गए। ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगहों पर परिवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही।

पीएम ने कहा कि सुल्तानपुर के सपूत श्रीपत मिश्र के साथ ही यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी भुला नहीं सकते। आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है, जो यूपी के सामान्य जन को अपना परिवार मानकर अपना काम कर रही है। यहां जो कारखाने लगे हैं, जो मिले हैं उनको चलाने के साथ-साथ नए निवेश के लिए माहौल बना रही है। आज यूपी में केवल पांच साल की योजना नहीं बनाई जा रही बल्कि इस दशक की जरूरतों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पूवी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी को पूर्वी और पश्चिमी तट से जोड़ने के पीछे यही सोच है। किसानों का उत्पाद दुनिया के बाजारों तक पहुंच पाएगा।

पिछली सरकार पर प्रहार

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब उन्हें सेवा करने का मौका मिला था तो यहां का सांसद होने के नाते, प्रधान सेवक होने के नाते उन्होंने बारीकियों से जानना शुरू किया। गरीबों को पक्के घर, शौचालय, बिजली, गैस सिलेंडर मिले ऐसे काम की जरूरत थी। लेकिन उस समय की सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े होने में भी उन्हें वोट बैंक नाराज होने से डर लगता था। मुझे मालूम था कि तब की सरकार ने योगी जी के आने से पहले यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। विकास सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखा। उन्होंने लोगों का आवाहन किया कि यूपी के लोग ऐसा करने वालों को यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे।

नए भारत के नए यूपी की तस्वीर

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस धरती पर हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, उस धरती की माटी में आजादी की लड़ाई की खुशबू आती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। महज तीन साल में ही इसका काम पूरा हो गया। बुंदेलखंड को भी नए एक्सप्रेस वे से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसी तरह पश्चिमी को पूर्वी यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का काम कुछ ही दिन में तैयार होने जा रहा है। 2017 तक उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही थे। आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट चल रहे हैं और 11 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है।

इससे पहले सुल्तानपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया और उन्हें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की रिप्लिका भेंट की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाएगा। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कोरीडोर बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेगे।.

जीवन रेखा है एक्सप्रेस-वे

उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेस वे की रफ्तार से विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रही है। सड़कों को विकास की जीवन रेखा माना जाता है। हालांकि, विकास तो ऐसा सफर है, जिसकी शायद मंजिल कोई नहीं। वह चलता रहेगा और नजर होगी सिर्फ अहम पड़ावों पर। जाहिर तौर पर हर सरकार ने अपनी-अपनी नीति-नीयत और रफ्तार से इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कनेक्टिविटी के मामले में कई 'मील के पत्थर' स्थापित किए हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पिछली दो सरकारों के कार्यकाल में एक-एक एक्सप्रेस-वे के सहारे प्रगति पथ पर चढ़े उत्तर

प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चार एक्सप्रेस-वे की सौगात देकर संभावनाओं के नए रास्ते खोले।

उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवस्थापना सुविधाओं के जरिये ईज आफ लिविंग की दिशा में काम शुरू किया। विकास का क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए हर अंचल को एक्सप्रेस रफ्तार देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और फिर गंगा एक्सप्रेस-वे का खाका खींचा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस वे लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा। 340.824 किमी लंबा ये एक्सप्रेस-वे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेस-वे लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होकर यूपी-बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले स्थित ग्राम हैदरिया जनपद गाजीपुर में समाप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सत्ता संभालने के बाद पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक सिक्स लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू करवाया था। इस एक्सप्रेसवे की लम्बाई 340.824 किमी है और इसे भविष्य में आठ लेन का किया जा सकता है. एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारे भी विकसित करने की योजना है।

क्या है परियोजना

एक्सप्रेस-वे 6 लेन चौड़ाई में है जो बाद में 8 लेन का किया जाएगा। इसकी डिजाइन इस तरह से की गई है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा के लिए 402 किलोमीटर का सर्विस रोड भी बनाया गया है। एक्सप्रेस वे पर 7 रेलवे ओवर ब्रिज 7 बड़े पुल 104 छोटे पुल, 271 अंडर पास और 526 पुलियों का निर्माण किया गया है। इन सभी स्थानों के लिए सोलर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। एक्सप्रेस वे का उपयोग करने वालों की सुविधा के लिए 8 प्रसाधन ब्लाक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 8 अन्य जन सुविधा परिसरों का निर्माण भी किया जाएगा। वाहनों में ईंधन भरने हेतु एक्सप्रेस वे पर 8 स्थानों पर फ्यूल पंप और चार स्थानों पर सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। पुलिस पेट्रोलिंग, कैटल कैचर वाहन और एम्बुलेंस वाहनों को भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक सुरक्षा हेतु एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाए गए हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के आकस्मिक उपयोग हेतु 34 मीटर चौड़ाई और 3.20 किलोमीटर लंबाई की हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 4.50 लाख पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 22497 करोड़ है जिनमें से 20408 करोड़ रुपये का व्यय करके 91 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

इन शहरों से निकलेगा एक्सप्रेस वे

ये एक्सप्रेस वे जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से होकर निकलेगा. सरकार का दावा है कि यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि क्षेत्रीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। मार्च, 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रदेश में केवल दो एक्सप्रेस वे ही मौजूद थे. अब इनकी संख्या में इजाफा होने को है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राज्य में एक्सप्रेस वे के निर्माण में उत्साह दिखाया है, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी. पिछले साल देव-दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' बन चुका है.

बिहार के लोगों को भी मिलेगा फायदा

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से न सिर्फ यूपी के बल्कि बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा. इसके बनने के बाद अब दिल्ली से बिहार तक का सफर भी आसान हो जाएगा। दरअसल, दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा, फिर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ तक का सफर पूरा होगा। इसके बाद लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गाजीपुर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। गाजीपुर से बिहार बार्डर की सीमा सिर्फ 20 किमी दूर है। ऐसे में अब इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद बिहार के लोगों के लिए भी दिल्ली दूर नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया तक इस एक्सप्रेसवे के विस्तार करने के निर्देश दिए हैं।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे

यह एक्सप्रेस वे जनपद चित्रकूट के ग्राम गोंडा (भरतकूप) के निकट झांसी-इलाहाबाद राजमार्ग से प्रारंभ होकर जनपद इटावा की तहसील ताखा के ग्राम उदरैल के समीप, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे में समाप्त होता है। यह एक्सप्रेस वे जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा जनपदों से गुजरेगा।

चित्रकूट से इटावा तक बन कुल 296 किमी के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 4 लेन का होगा जो बाद में 6 लेन किया जाएगा। प्रवेश एवं निकासी हेतु 11 सीनों पर इंटरचेंज सुविधा दी गई है। आस पास के गांवों को सुगम आवागमन की सुविधा के लिए सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे में 4 रेलवे ओवर ब्रिज, 14 बड़े पुल, 139 छोटे पुल, 220 अंडर पास का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए 5 जन सुविधा परिसर और वाहनों में ईंधन भरने के लिए 4 सीनों पर फ्यूल पंप सीपित किए जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर 3 लाख पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 14849.02 करोड़ रुपये है जिसमें से 8351.27 करोड़ रुपये व्यय करके 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। यमुना, बेतवा और केन नदी पर पुलों का निर्माण भी चल रहा है। चार लेन चौड़े इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में छह लेन का भी किया जा सकता है।

गंगा एक्सप्रेस वे

मेरठ-बुलंदशहर मार्ग पर जनपद मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर यह एक्सप्रेस वे प्रयागराज बाईपास के जूड़ापुर दांदू गांव के समीप समाप्त होगा। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर जाएगा। 6 लेन के इस एक्सप्रेस वे पर प्रवेश और निकासी हेतु 17 स्थानों पर इंटरचेंट की सुविधा है। एक्सप्रेस वे पर 7 रेलवे ओवर ब्रिज, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल और 381 अंडर पास बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपात काल में वायुसेना के विमानों हेतु जनपद शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी विकसित की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत 36229.67 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 94 प्रतिशत हो चुका है। यह एक्सप्रेस वे पश्चिम को पूरब से जोड़ेगा। एक्सप्रेस वे कुल 594 किमी लंबा होगा। मेरठ से प्रयागराज को सीधे जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे

यह एक्सप्रेस वे गोरखपुर के ग्राम जैतपुर से प्रारंभ होता है और आजमगढ़ के ग्राम सलारपुर में समाप्त होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से मिल जाता है। एक्सप्रेस वे जनपद गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ता है। 91.352 किमी का यह एक्सप्रेस वे 4 लेन है जो बाद में 6 लेन किया जाएगा। इस पर प्रवेश और निकासी हेतु 7 सीनों पर इंटरचेंज सुविधा दी गई है। आस पास के गांवों के सुगम यातायात हेतु सर्विस रोड़ बनाया जा रहा है। एक्सप्रेस वे पर 8 बड़े पुल, 13 छोटे पुल, 100 अंडर पास और 141 छोटी पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 2 जन सुविधा केन्द्र भी बनाया जा रहा है। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 1.20 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसकी लागत 5876.68 करोड़ रुपये है जिसमें से 3047.3 करोड़ रुपये व्यय करके 30 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। मार्च 2022 तक इस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के अवशेष कार्य पूर्ण

प्रवेश नियंत्रित 6 लेन की 302.222 किमी का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आगरा इनररिंग से प्रारंभ होकर जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई और उन्नाव होते हुए लखनऊ मोहान रोड

पर मिल जाता है। एक्सप्रेस वे का निर्माण 5 पैकेजों में किया गया है। पिछली सरकार द्वारा बनाए गए इस एक्सप्रेस वे के बचे हुए कार्य को वर्तमान सरकार ने पूरा किया। अपूर्ण कार्यों में मुख्य रूप से एक्सप्रेस वे की मुख्य कैरेज वे की 800 मीटर लंबाई में तारकोल कंकरीट, एक बड़ा पुल, 4 इंटरचेंज, 24 किमी लंबाई में क्रैस वैरियर, 38 किमी लंबाई में रोड मार्किंग, 203 किमी में रोड़ साइनेज लगाने का कार्य, 12 किमी मीडियन फेसिंग, 126 किमी आरओडब्ल्यू फेसिंग का कार्य शेष था। जिसे वर्तमान सरकार द्वारा पूरा किया गया। इसी तरह से सर्विस रोड का कार्य, यात्रियों की सुविधा के लिए सुविधा परिसर का कार्य भी अधूरा था। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ दो-दो फ्यूल स्टेशन स्थापित किया गया।

जमीन पर उतरा हवाई अड्डों का काम

योगी सरकार अपनी उपलब्धियों में इस तथ्य को बार-बार उभारती है कि वर्ष 2017 तक केवल चार एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा थे। वर्तमान सरकार ने प्रयागराज, कानपुर, हिंडन और बरेली हवाई अड्डे से उड़ान शुरू कराई। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान के लिए तैयार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना शुरू हो गया। कुल मिलाकर 13 हवाई अड्डे और एक हवाई पट्टी का काम प्रगति पर है। इनमें अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट जल्द शुरू होंगे। इसी तरह लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो चल रही है। आगरा और कानपुर में काम चल रहा है। मेरठ को मेट्रो की सौगात योगी सरकार ने दी है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में भी जल्द शुरुआत होगी। ❑

किसे चोट पहुँचायेगा जिन्ना का जिन्न

गोविन्द पंत राजू
9415014980

ज्यों ज्यों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धर्म, राजनीति, आतंक, अपराध और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को हवा देने लगे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के बारे में यह माना जाता है कि यहां चुनाव में जमीनी मुद्दों की तुलना में धर्म और जाति जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावकारी रहते हैं और तमाम राजनीतिक दल अपनी चुनावी फायदे के लिए इन मुद्दों को धार देते रहते हैं। लेकिन इस बार के चुनावों में ऐसा लग रहा है कि धर्म और सांप्रदायिकता के मुद्दे बड़े मुद्दे बनकर उभरने वाले हैं। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से ब्राह्मण सम्मेलन और फिर उसी की तर्ज में समाजवादी पार्टी ने भी ऐसे ही सम्मेलन करने शुरू किए थे। बीएसपी में नंबर दो के नेता सतीश मिश्रा ने तो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ही अयोध्या में दर्शन और स्नान करके की थी। समाजवादी पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए और ब्राह्मणों की योगी सरकार से कथित नाराजगी का लाभ उठाने के लिए परशुराम जयंती ,परशुराम की मूर्ति और परशुराम जयंती पर अवकाश की घोषणा जैसे वायदों को हवा देने लगी थी । ए आई एम आई एम के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को एक अलग वोट बैंक की तरह संगठित करने की कोशिशों में जुटे हुए थे मगर हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर एक नया ही दांव खेल दिया।

हालांकि यह दांव अखिलेश यादव को भारी पड़ता दिख रहा है क्योंकि बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने अखिलेश यादव के इस बयान पर खूब लानत मलानत शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक कार्यक्रम में यह कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने एक ही संस्थान से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी और इन चारों का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बीजेपी ने मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना गांधी, पटेल और नेहरू से करने की अखिलेश यादव की कोशिश पर तीखा हमला बोला था और इसे सरदार पटेल का अपमान बताया था क्योंकि यह बयान सरदार पटेल की जयंती वाले दिन ही दिया गया था। इस बयान पर कांग्रेस और बीएसपी की प्रतिक्रिया भी बहुत तीखी थी। ओवैसी ने तो इस बयान को लेकर अखिलेश यादव की इतिहास की जानकारी और राजनीतिक समझ पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि जिन्ना कभी भी भारत की जनता के नायक नहीं रहे। चारों लोगों के एक ही संस्थान से कानून की शिक्षा लेने वाले बयान पर भी बुद्धिजीवियों ने यह कहकर एतराज जताया कि इन चारों ने एक ही संस्थान से कानून की शिक्षा नहीं हासिल की थी। यानी कि अखिलेश यादव का बयान ऐतिहासिक संदर्भों में तो गलत

था ही, वह तथ्यात्मक रूप में भी सही नहीं था। आम मुस्लिम मतदाता में भी इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि इस बयान के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि अखिलेश यादव यह साबित करना चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के नायक अभी भी मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं और जिन्ना की तारीफ करके उन्होंने आम भारतीय मुस्लिम मतदाता के लिए भी बहुत असुरक्षा और अपमान की स्थिति बना दी है। वरिष्ठ बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन कहती हैं कि ''जिन्ना कभी भी भारत के मुस्लिमों के नायक नहीं रहे। असल बात तो यह थी कि जिन्ना अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली में भी मुस्लिम नहीं थे इसलिए यदि अखिलेश यादव ने यह बयान उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए दिया है तो निश्चित रूप से यह उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक चूक है और उन्हें अपने इस बयान का प्रतिवाद करना चाहिए, इस बयान पर सफाई देनी चाहिए। ''लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से इस बयान पर किसी भी तरह की सफाई नहीं आई उल्टे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यह कह कर अखिलेश के बयान के समर्थन में जुट गए कि जिन्ना से स्वराज की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा 1908 व 1916 में दो बार लड़ा था। अब समाजवादी पार्टी के नए नए सहयोगी बने ओमप्रकाश राजभर ने अपने बेतुके और मूर्खता भरे बयानों से अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान का समर्थन किया है और उस बयान को एकदम सही ठहरा कर रही-सही कसर भी पूरी कर दी है।

पूर्व सैनिक अधिकारी कर्नल फसी अहमद मानते हैं कि ''यह बयान भारत के आम मुसलमान को और देश के प्रति उसकी निष्ठा को संदेह के दायरे में लाने वाला है। 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति से इस तरह का बयान निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि या तो अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ बिल्कुल शून्य है और या फिर उनके सलाहकार निश्चित रूप से बहुत निकृष्ट कोटि के लोग हैं । उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए जिन्ना को मुद्दा बनाने की कोशिश निहायत बेवकूफी भरी है।''

अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को भी बैठे बिठाए एक नया मुद्दा दे दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने अखिलेश यादव के इस बयान के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि

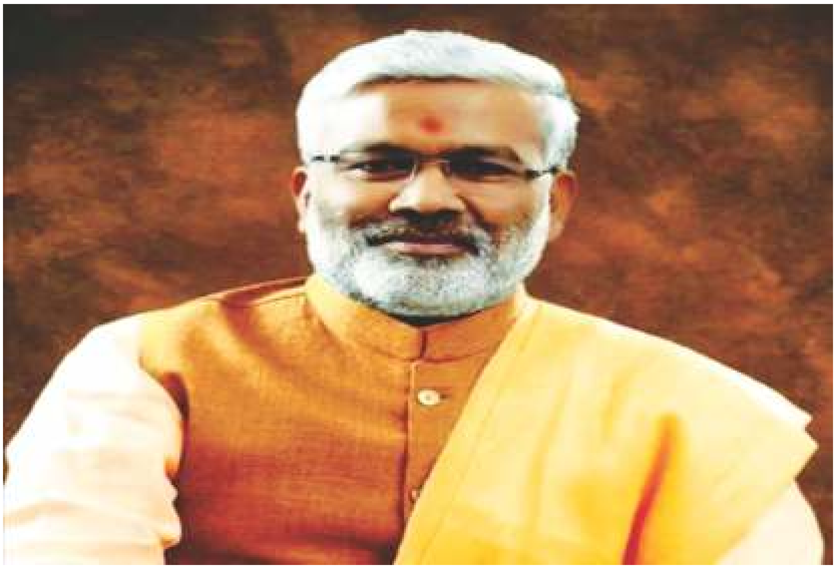

जिस तरह अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की है वह देश के लिए शर्म की बात है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना को घसीटना यह दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव किस हद तक नीचे गिरने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की समझदार जनता अवश्य अखिलेश यादव को उनके इस बयान के लिए सबक सिखाएगी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो अखिलेश यादव के इस बयान ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया। योगी अब अपनी हर सभा में जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश यादव को अवश्य घसीटते हैं। वे इस बहाने अखिलेश सरकार अक्षम और अलोकतांत्रिक बताने से भी नहीं चूकते। कैराना, बदायूं और शाहजहांपुर की अलग-अलग सभाओं में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी कि अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इन सभाओं में योगी ने कहा कि सपा सरकार में दंगे होते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे और दंगाइयों को सीएम आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। पहले सैफई में नाच गाना होता था, आज अयोध्या में दीपोत्सव होता है। योगी कहते हैं कि जब 2012 में सपा सरकार बनी तो कोसीकलां, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर आदि जगहों में दंगे हुए। पहले आतंकियों और दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को यातनाएं झेलनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। दंगाइयों को उनकी भाषा में जवाब देकर कैसी कार्रवाई की जाती है, यह यूपी की भाजपा सरकार ने पूरी दुनिया को दिखाया है। योगी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करना भी अपनी सभाओं में नहीं भूलते।

अखिलेश यादव के बयान और उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया से अचंभित बीएसपी नेता मायावती भी चुनावों से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए सपा और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप लगाकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। मायावती ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि सपा और भाजपा के बीच मिलीभगत है और दोनों पार्टियां अंदरूनी तौर पर मिली हुई हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले जिन्ना, अयोध्या पुलिस फायरिंग और मुजफ्फरनगर दंगों जैसे गड़े मुर्दों को उखाड़ कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाने की राजनीतिक दलों की कोशिश के पीछे कई वजहें देखते हैं। पहली वजह तो समाजवादी पार्टी की विपक्षी दल के रूप में पिछले 5 वर्षों की भूमिका है। यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पिछले 5 वर्षों में विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल रही है। न तो वह सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर ही कोई प्रभावशाली भूमिका निभा पाई और न ही प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते राज्य की जनता की

आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शित कर पाई। विपक्ष के नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता के बीच सक्रिय होने के बजाय अपना ज्यादातर समय रनिवास में ही बिताते रहे। इसलिए अब चुनाव सर पर आने और फिर से सत्ता पाने की प्रत्याशा में समाजवादी पार्टी हताश होती जा रही है और इसलिए वह हड़बड़ी में जिन्ना जैसे बेतुके मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी भले ही यह दावा करती रही हो कि उसके आने के बाद उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत में बड़ा सुधार आया है ,उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश आज पूंजी निवेश के मामले में देश में पहली पसंद बनता जा रहा है लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्थव्यवस्था और पूंजी निवेश जैसे सवाल आम आदमी को इसलिए प्रभावित नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका असर अभी आम आदमी पर पड़ना शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह कानून व्यवस्था का मुद्दा सरकार के दावों और उत्तर प्रदेश पुलिस के आपराधिक चरित्र तथा रोज-रोज राज्य के अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध जैसे कारणों से आम आदमी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। 2 वर्ष के कोरोना काल ने भी उत्तर प्रदेश के विकास और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में काफी बाधा डाली है। इस वजह से बीजेपी सरकार सिर्फ इन्हीं मुद्दों के बूते पर उत्तर प्रदेश में जीत के प्रति आश्वस्त नहीं दिखाई देती और यही वजह है कि वह अयोध्या में मंदिर निर्माण ,दीपोत्सव, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के कायाकल्प और कुशीनगर, मथुरा आदि इलाकों में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के साथ-साथ अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिशों में सेंध लगाने के लिए कट्टरपंथी हिंदू प्रतिक्रियावाद को आगे बढ़ाने में कोई चूक नहीं कर रही। बहुजन समाज पार्टी को भी सांप्रदायिकता के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वोट बैंक को और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने का प्रयास करना चाहती है। कांग्रेस ने अपने कमजोर संगठन के बावजूद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐसे मुद्दों से दूर रहने की कोशिश की है लेकिन उसके पूर्व केंद्र केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या : नेशनहुड इन अवर टाइम्स' में हिंदू कट्टरवाद को बोको हरम और इस्लामिक स्टेट जैसे मुस्लिम आतंकी संगठनों के साथ खड़ा कर देने की कोशिश के बाद बीजेपी ने जिस तरह से हमलावर रुख अपनाया है उसके चलते उसे भी अब इस मामले में अपना रुख साफ करना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की टिप्पणी को खारिज करके इस दिशा में पहल भी कर दी है लेकिन इससे कांग्रेस की समस्या खत्म नहीं होने वाली क्योंकि उसके एक और नेता राशिद अल्वी ने भी न सिर्फ खुर्शीद के बयान का समर्थन किया है बल्कि जय श्रीराम कहने वालों पर भी विवादित टिप्पणी कर दी है और अब तो राहुल गांधी भी सलमान खुर्शीद की ताल में ताल मिलाने लगे हैं।

राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता को हथियार बनाने की इन तमाम कोशिशों का सबसे बड़ा खामियाजा हर हाल में उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं ,जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो जरूरत हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के जो बड़े मुद्दे हैं वह सांप्रदायिकता के इन निरर्थक सवालों के बीच कहीं धुंधला जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से अपने ठगे जाने का एहसास होगा । चुनाव की जीत के बाद सत्ता भले ही किसी के हाथ में आए जनता के हिस्से झुनझुना ही आने वाला है। ❑

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

किस करवट बैठेगा जनमत का ऊँट

रामसागर शुक्ल
9839126463

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अभी चुनाव में लगभग चार माह हैं पर राजनीतिक दलों की सक्रियता देखकर लगता है जैसे चुनाव कल ही होने वाला है। इस चुनाव में किसको विजयश्री मिलेगी, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि पिछले चुनाव अर्थात 2017 में क्या स्थिति थी। सत्तारूढ़ भाजपा को लग रहा है कि 2022 के चुनाव में भी जनता उन्हें ही फिर सत्तारूढ़ करेगी। परन्तु यह कही अति आत्मविश्वास तो नहीं है। 2015 के चुनाव में भाजपा विपक्ष में थी जबकि इस बात सत्ता में है। पिछले चुनाव के मुकाबले आने वाले चुनाव में स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं।

2017 के चुनाव में सपा सत्ता में थी। लोग उससे नाराज थे। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अचानक नोटबंदी करके विपक्ष की कमर तोड़ दी थी। नोटबंदी की घोषणा होते ही सपा के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए प्रधानमंत्री से कहा कि कम से कम एक सप्ताह के लिए नोटबंदी टाल दी जाए। बहुजन समाजपार्टी का अध्यक्ष कु. मायावती ने भी पार्टी के लिए चंदा लेकर जिनको टिकट दिए थे उनके चंदे लौटा दिए। उन्होंने अपने अमीर पार्टी से कहा कि नये नोटों में चंदा देकर टिकट लें। सपा और बसपा दो प्रमुख पार्टियां थीं उस समय। नोटबंदी ने इन्हें आर्थिक तौर पर कंगाल और कमजोर कर दिया। इसका प्रभाव चुनाव पर भी पड़ा। सपा और बसपा के आर्थिक रूप से कमजोर होने से भाजपा को लाभ मिला क्योंकि भाजपा भले ही उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं थी परन्तु केन्द्र में सत्तारूढ़ थी। अतः उसे चुनाव में पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ा।

पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति के हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने की आशा में पिछड़ी

जातियों के मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। पिछले चुनाव में यह लगभग तय था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री होंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछड़ी जाति के मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। उस चुनाव के दौरान अमेरिका से मेरे मित्र ने पूछा कि किस पार्टी की जीत की संभावना है तो मैने कहा कि इस बार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग तय है। फिर उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो उस समय का जैसा माहौल था उसके अनुसार मैने कहा कि नहीं केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है। परन्तु हुआ कुछ और। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस प्रकार का कानून आधी रात को नोटबंदी लागू कर दी उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा में इतनी मजबूत स्थिति है कि उनके निर्णय का कोई विरोध नहीं कर सकता था। भाजपा विधायक दल में केशन प्रसाद मौर्य का विधायक दल में केशव प्रसाद मौर्य का बहुमत था किन्तु मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ। योगी जी उस समय विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। बाद में उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। योगी जी लोकसभा के सदस्य थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव था। परन्तु गोरखपुर के बाहर उनका कोई खास प्रभाव नहीं था। परन्तु प्रधानमंत्री का कृपा पात्र होने के कारण किसी विधायक ने उसका विरोध नहीं किया। अब पांच वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद संभव है कई विधायक उनके समर्थक हो गए होंगे।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या और गोरखपुर का दौरा किया। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी लखनऊ आये थे। इन दोनों ही नेताओं ने आमसभा में कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगला चुनाव भाजपा के झंडे पर लड़ा जाएगा। इसका कुछ लोग अर्थ लगा रहे हैं कि पांच साल बाद भी केशव जी को योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व पसंद नहीं है। इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है।

पिछड़े वर्ग के जिन मतदाताओं ने पिछले चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में भाजपा को वोट दिया था वे अब भाजपा से निराश होकर दूसरे दल के साथ जा सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हिंदुत्व के लिए निःसंदेह अच्छा कार्य किया है। विशेषकर अयोध्या और वाराणसी का यथेष्ट विकास किया है। वास्तव में वे देश में हिंदुत्व के सब से बड़े चेहरे के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि मुसलमान तो उन्हें कतई वोट नहीं देंगे। पिछले चुनाव में तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने के कारण भारी संख्या में मुसलमान महिलाओं ने भी भाजपा को वोट दिया था। परन्तु इस चुनाव में ये महिलाएं भाजपा को वोट देंगी ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है। जैसा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के भाषण से लग रहा है कि इस बार कई वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इससे पार्टी में असंतोष की लहर फेल सकती है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काफी सक्रिय हैं। यह भी भाजपा के लिए खतरा बढ़ा सकता है। योगी जी के स्वभाव के कारण पूर्वांचल में ब्राहमण मतदाता उनके नाराज हैं परन्तु वे मोदी के विरोधी नहीं हैं। फिर भी अगर प्रियंका का प्रभाव बढ़ा तो पूर्वांचल में ब्राहमण मतदाता कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। बसपा की स्थिति कुछ कमजोर हुई लगती है परन्तु उसके अपने मतदाता अभी भी उसके साथ हैं। सपा के अपने मतदाता भी उसके साथ हैं। इस प्रकार आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है।

भाजपा की जीत निश्चित है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सहारा है। अभी चार माह में इस बीच राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका भी प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा पार्टी का आंतरिक कलह है। इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। ❑

मुश्किल में सांस!

राजेश माहेश्वरी
9415032541

दीपावली का त्यौहार देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा और देश के अलग-अलग हिस्सों में जमकर पटाखें जलाए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि चारों ओर आसमान में प्रदूषण ही प्रदूषण फैल गया। देश की राजधानी समेत देश के कई शहरों में पटाखों के धुओं से हवा बेहद प्रदूषित हो गई। दीपावली के पांच दिनों बाद भी हवा अभी साफ नहीं हुई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में वायु काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। चारों ओर प्रदूषण की वजह से कोहरा सा छाया हुआ है। दिल्ली सरकार ने पटाखों की ब्रिकी और उन्हें जलाने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम सड़कों पर पटाखे फोड़े। शुक्रवार सुबह दिल्ली के जनपथ में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर मापी गई। पीएम 2. 5 का स्तर 655.07 तक पहुंच गया। सरकारी मानकों के मुताबिक, पीएम 2.5 का स्तर 380 के ऊपर जाना ही गंभीर माना जाता है। शुक्रवार को दोपहर 3.07 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 531 पर मापा गया।

हर साल दिल्ली और देश के कई शहरों की यही हालत होती है। हर बार पर्यावरण बचाने की बातें की जाती हैं और हर बार त्यौहार के समय हालात चिंताजनक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम अदालत ने पटाखों पर रोक लगाई। उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखा। इस बार बाजार में ज्यादा आवाज और धुआं फैलाने वाले पटाखे कम ही दिखे। ग्रीन पटाखों की मात्रा बाजार में इस बार पहले से ज्यादा दिखी। काफी कुछ बदला है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से अभी काफी कुछ बदलने की जरूरत अनुभव हो रही है।

यूपी में नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर वन पर है तो वहीं वाराणसी की हवा सबसे साफ है। कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में भी स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर एक्यूआई 200 के ऊपर है जिसे पुअर की कैटेगरी में डाला गया है। चंडीगढ़ में शहर में प्रशासन के आदेश का पालन कराने के लिए 600 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए थे मगर कहीं भी उनका कोई डर नजर नहीं आया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। 4 नवंबर की रात लोगों की ओर से चलाए गए पटाखों के धुएं की वजह से 5 नवंबर को चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 प्वाइंट पर पहुंच गया। लखनऊ में प्रदूषण की वजह से पिछले चार दिन से धुंध सी छाई हुई है। चेन्नई पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 758 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिन्होंने पटाखे चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने पर बैन लगाया था। पटाखों की बिक्री करने वाली 239 दुकानों पर भी केस किया गया है। मध्य प्रदेश के कटीनी शहर में भी दीवाली में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। पटाखा जलाने का ही नतीजा था कि शहर का प्रदूषण स्तर 100 से अचानक 160 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। पटाखों के जलने से निकलने वाले धुएं का गुबार आसमान में बन गया था।

हवा की क्वालिटी मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ईकाई है, जिसके आधार पर पता चल जाता है कि उस स्थान की हवा कितनी साफ है और सांस लेने योग्य है या नहीं. इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जिससे समझ आ जाता है कि उस स्थान की हवा में कितना प्रदूषण है। दरअसल, एयर क्वालिटी इंडेक्ट में 8 प्रदूषक तत्व को देखा जाता है कि उनकी मात्रा कितनी है। अगर उनकी तय लिमिट से ज्यादा मात्रा होती है, तो समझ जाता है कि वहां की हवा प्रदूषित है। इन तत्वों में सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन डाइआक्साइड और कार्बन मोनोआक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंड से अलग नहीं होना चाहिए। हवा की गुणवत्ता के आधार पर इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी होती है। इसमें अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर जैसी कैटेगरी शामिल हैं। अगर अच्छी रैंकिंग की बात करें तो इसमें 50 से कम होना चाहिए। इसके बाद ये स्तर बढ़ता जाता है और 500 से ऊपर हो जाता है तो यह एक इमरजेंसी की स्थिति है और इससे सांस संबंधी दिक्कत होने का खतरा बढ़ जाता है और लोगों को सलाह दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें। दिल्ली में इंडिया गेट, नेशनल स्टेडियम, पटपड़गंज, श्रीनिवासपुरी, शाहदरा, आनंद विहार, ओखला और सोनिया विहार आदि स्थानों के अलावा गाजियाबाद और नोएडा सरीखे आसपास के इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 999 तक पहुंच गया था। यह अत्यंत भयावह

और जानलेवा बिंदु है।

एम्स के निदेशक डा० रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि ऐसा प्रदूषण राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ा सकता है। दोनों का मानवीय फेफड़ों से सीधा संबंध है। प्रदूषण बढ़ने से मुख्य रूप से अस्थमा से पीड़ित मरीजों को परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा की बीमारी से पीड़ित होने की आशंका अधिक रहती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, 100 तक का एक्यूआई सामान्य और अच्छा माना जाता है। उसके बाद तो हवाएं जहरीली होनी शुरू हो जाती हैं।

दिल्ली में पटाखों के अलावा पराली के धुएं ने भी जानलेवा स्थिति पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन ही करीब 40 फीसदी प्रदूषण पराली के हिस्से दर्ज किया गया। इसके अलावा औद्योगिक, निर्माण-कार्यों, परिवहन और अन्य कारणों से भी प्रदूषण फैलता और बढ़ता रहा है। पटाखे आग में घी का काम करते रहे हैं। दिल्ली का वायु प्रदूषण भयावह स्तर को छूकर लौट रहा है। प्रदूषण का यह सिलसिला अब जनवरी माह के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। तब तक न तो पराली जलाई जाती है और न ही पटाखेबाजी होगी। जो प्रदूषण बाहरी इलाकों से आकर दिल्ली की हवा में घुल-मिल गया है, उसका प्रभाव फरवरी तक भी महसूस किया जाता रहा है। पिछले कई सालों से अनुभव किया है कि हर साल अक्तूबर माह से प्रलाप शुरू होता है। सरकारें और विपक्ष अलग-अलग स्वरों में प्रलाप करते हैं। सर्वोच्च अदालत भी पटाखों पर पाबंदी के साथ-साथ तल्ख टिप्पणियां करती रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार तरह-तरह के रोने रोती है।

लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार दिखाई नहीं देता।

दिल्ली सरकार ने भी करोड़ों रुपए खर्च करके स्माग टावर स्थापित किए थे। वे भी प्रदूषण को नहीं रोक पाए। राज्य सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट में पराली के संदर्भ में डिकंपोजर के प्रयोग कराए थे। फिर भी दिवाली के आसपास 3500 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई। स्वाभाविक है कि उसका धुआं दिल्ली के पर्यावरण को छलनी करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए ताकि करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। इस मामले में सियासत होना भी बड़ा चिंताजनक पहलू है। पर्यावरण के मामले में सभी दलों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बारे में सोचना होगा तभी दिल्लीवासी चैन की सांस ले पाएंगे।

देश का सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन

रानी पद्मावती से कम नहीं है रानी कमलापति का जौहर

भोपाल में बने भारत के सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आज यह रेलवे स्टेशन किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मात देता है। लेकिन हम स्टेशन की भव्यता की नहीं बल्कि उसकी दिव्यता की बात करेंगे, और दिव्यता इस रेल्वे स्टेशन के नाम में है।

जब भोपाल के इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखे जाने का समाचार लोगों ने सुना तो शेष भारत तो छोड़िये, मध्यप्रदेश भी जाने दीजिये, भोपाल के नागरिकों तक को भी आश्चर्य हुआ कि ये रानी कमलापति कौन थी? भोपाल को तो नवाबों ने बसाया है, भोपाल में किसी हिन्दू राजा का नाम अगर सुना वो राजा भोज का सुना, तो फिर ये रानी कमलापति कहां से आ गई? और रानी कमलापति कौन है? यदि स्टेशन के नामान्तरण के बाद यह प्रश्न आपके भी मन में उठा हो, तो समझिये पिछले एक शतक के षड्यंत्र के परिणाम आंशिक रूप से आपके मस्तिष्क पर भी हुए हैं। वे हमें हमारी जड़ों से काटना चाहते थे और कुछ भी कहो वे कुछ हद तक सफल तो हुए हैं। खैर, रानी कमलापति को मध्यप्रदेश की पद्मावती भी कह सकते हैं। जैसे पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया था, ठीक वैसे ही रानी कमलापति ने भी जलसमाधि ली थी।

सोलहवीं सदी में समूचे भोपाल क्षेत्र पर हिन्दू गोंड राजाओं का ही शासन था। कमलापति गोंड राजा निजामशाह की पत्नी थीं। भोपाल के पास गिन्नौरगढ़ से राज्य का संचालन होता था। फिर गद्दी का मोह कुटुंबियों में आया।राजा निजामशाह के भतीजे आलमशाह, जिसका बाड़ी पर शासन था, के मन में गिन्नौरगढ़ को हड़पने का विचार आया। लड़ तो सकता नहीं था, तो घटिया हरकत की, निजामशाह को खाने पर बुलाया ,खाने में जहर मिलाया और राजा को परलोक पहुंचाया।

रानी अपने बेटे नवलशाह की रक्षा के लिए बेटे को लेकर गिन्नौरगढ़ से भोपाल आ गई। भोपाल के छोटे तालाब के पास रानी का महल था। रानी ने अफगानिस्तान से आये हुए मोहम्मद खान से अपने पति के हत्यारे आलमशाह को सबक सिखाने की बात की, मोहम्मद खान एक लाख रुपये के बदले काम करने को तैयार हुआ और उसने आलमशाह को मौत के घाट उतार दिया। पर रानी के पास उस समय धन की पूरी व्यवस्था न हो पाने के कारण रानी ने भोपाल का एक हिस्सा मोहम्मद खान को दे दिया।

किन्तु कुछ समय बाद मोहम्मद खान की भी स्वार्थी और विश्वासघाती वृत्ति बड़ी होकर सामने आ गई। उसकी नीयत पूरे भोपाल पर कब्जा करने की थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि रानी पर भी उसकी कुदृष्टि थी।आखिरकार रानी के चिरंजीव नवलशाह और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ ,युद्ध अत्यंत भयानक था। इतना कि जिस घाटी पर युद्ध हुआ वो खून से लाल हो गई, भोपाल में आज भी उसे लालघाटी कहते हैं। रानी माता की मानरक्षा के लिए अन्य सैनिकों के साथ नवलशाह का भी बलिदान हो गया। अंत में केवल दो लोग बचे, उन्होंने लालघाटी से धुँआ छोड़ा ,,महल में बैठी रानी इसका अर्थ समझ गईं। उन्होंने अपने निजी सेवकों को तालाब की नहर का रास्ता अपने महल की ओर मोड़ने के आदेश दिए। रानी अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ महल के सबसे नीचे वाले तल में जाकर बैठ गईं और अपने शील की रक्षा के लिए जल-समाधि ले ली।

इसे जल-समाधि की जगह जल-जौहर भी कह सकते हैं। जैसे रानी पद्मिनी के साथ अगणित महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था, वैसा ही रानी कमलापति ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया।

आज भी रानी के महल की पांच मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं, केवल दो मंजिलें ही पानी से बाहर हैं, ऐसी न जाने कितनी कमलापतियों का इतिहास उस महल की तरह ही अँधेरे में डूबा हुआ है। उन पर अब प्रकाश जाने लगा है और दुनिया उससे आलोकित होने लगी है। वरना देश में छः से ज्यादा महापुरुष ही नहीं हुए, ऐसा लगने लगा था, हर नगर में, हर गांव में उनके ही नाम के संस्थान, चौराहे सब हुआ करते थे। किन्तु अब हमारे स्थानीय महापुरुषों के नाम पर विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाने लगा है यह सच में सत्य के उद्घाटन का समय है।

कांग्रेस का महिलाओं पर दांव

46 प्रतिशत महिला वोट पर नजर

प्रभप्रीत सिंह
8299590418

आने वाले दिनों में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आधी आबादी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा का दांव चलते हुए अन्य दलों में बेचैनी पैदा करने का काम किया है।

यह घोषणा करते हुए कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं सत्ता में पूरी तरह भागीदार बनें। महिलाएं अगर समाज में बदलाव चाहती हैं तो राजनीति में आएं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। प्रियंका बोलीं मेरी लड़ाई नई राजनीति के लिए है। मेरी लड़ाई उन महिलाओं और पीड़ितों के लिए है जो अपनी पीड़ा के लिए आवाज नहीं दे पाती हैं। यह लड़ाई इसके लिए है कि कोई भी सत्ता का दुरूपयोग कर किसी को कुचल न पाए।

प्रियंका ने कहा कि जब मैं 2019 में यूपी की प्रभारी बनकर यहां आई थी तो कुछ छात्राओं ने मुझसे कहा था कि विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग नियम कायदे बने हुए हैं। इसलिए हमारा यह निर्णय उन महिलाओं के लिए है जो पीड़ित हैं या दुश्वारियों का सामना कर रही हैं और बदलाव चाहती हैं। यह निर्णय प्रयागराज की उस पारो के लिए है जो बड़ी होकर नेता बनना चाहती है। चंदौली के शहीद की उस बहन के लिए है जो बड़ी होकर पायलट बनना चाहती है। उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसे जलाया गया और उसकी भाभी की बेटी को स्कूल में धमकाया गया। हाथरस की उस बेटी के लिए है जिसके साथ अन्याय की सारी हदें

लड़की हूं लड़ सकती हूं

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कई प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा का पहला नारा - 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' है। यह घोषणा करने के लिए जब वह मीडिया के सामने आईं तो उनके साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना और दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत थीं। इससे यह संदेश साफ था कि भागीदारी को लेकर उनके इरादे पक्के हैं।

कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया के समक्ष आने से पहले उनके इशारे पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का बैनर जहां लगाया गया वहीं उनके आने के पहले वहां महिलाओं का बड़ा हुजूम भी आ चुका था। प्रियंका ने आने पर महिलाओं के हुजूम से यह नारा भी लगवाया।

पार कर दी गईं। लखनऊ की उस लड़की के लिए है जो बीए और आईटीआई करने के बावजूद नौकरी नहीं पा सकी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली उन सभी महिलाओं के लिए है जो बदलाव चाहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को राजनीति में आना होगा। मैं तो चाहती थी कि 50 फीसदी टिकट महिलाओं को दिए जाएं। लेकिन पार्टी में चर्चा के बाद 40 फीसदी पर सहमति बनी है।

आज सत्ता के नाम पर आप खुलेआम पब्लिक को कुचल सकते हैं। आज नफरत का बोलबाला है। महिलाएं इसे बदल सकती हैं। राजनीति में आप मुझसे कंधे से कंधा मिलाइए यूपी में बदलाव का सपना पूरा होगा। देश को विकास की ओर आगे ले जाना है तो भागीदारी के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। मैं चाहती हूं कि यूपी की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। कांग्रेस टिकट जाति नहीं मेरिट के आधार पर देगी। महिलाएं एकजुट होकर कार्य करें जाति धर्म में बंटकर नहीं।

यह तो साफ है कि प्रियंका की यह घोषणा महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। जब महिलाओं की निर्णयों और उच्च पदों पर भागीदारी बढ़ेगी तब निश्चय ही महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। कांग्रेस का यह फैसला चौंकाने वाला भी है और महिलाओं के हित में भी है। लेकिन यूपी में कांग्रेस की जो राजनीतिक स्थिति है उसको देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि इसका महिलाओं की स्थिति पर इतना असर पड़ेगा। यह जरूर है कि कांग्रेस के इस फैसले से अन्य राजनीति दलों पर दबाव बढ़ गया है।

प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पत्रकारों, समाजसेवियों, डॉक्टरों समेत अन्य महिलाओं का आवाहन किया कि जो भी महिलाएं इच्छुक हैं वे अपने विधानसभा से फार्म लेकर आवेदन कर सकती हैं। अगर किसी पूर्व सांसद या जिलाध्यक्ष की बहन, बेटी या पत्नी चुनाव लड़ती है तो भी कोई बुराई नहीं है। शुरूआत कहीं से तो होनी चाहिए। आगे चलकर वे सक्षम हो जाएंगी।

कांग्रेस ने यह दांव चल कर अन्य दलों को चिंतित जरूर कर दिया है लेकिन खुद वह उधेड़बुन में है। क्योंकि कांग्रेस के लिए 160 से ज्यादा सीटों पर सशक्त महिला उम्मीदवार खोजना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस घोषणा का असर कांग्रेस पर ही क्या पड़ता है। ❑

अभी तक अधिकतम 40 महिलाएं ही पहुंची हैं विधानसभा तक

महिलाओं को लेकर राजनीतिक दल भले ही बड़ी-बड़ी बातें करते हों लेकिन हकीकत यह है कि 30 फीसदी के आरक्षण जैसी बातों को खूब जोर देकर कहने के बावजूद टिकट देने में किसी भी दल ने दरियादिली नहीं दिखाई है। ऐसे में कांग्रेस का 40 फीसदी महिलाओं को टिकट देने की घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है।

वास्तविकता यह है कि 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देने की बात तो बड़ी दूर की है जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 40 महिला विधायक थीं ही चुनी जा सकी थीं। जिसमें से दो कांग्रेस की थीं। इनमें एक आराधना मिश्रा मोना और दूसरी अदिति सिंह थीं। इसी तरह पिछली विधानसभा यानी 2017 में महिलाओं को भाजपा ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। भाजपा के टिकट पर 46 महिलाएं लड़ी थीं जिनमें से 34 महिला सदन में पहुंचने में सफल हुई थीं। लेकिन भाजपा ने भले ही 46 महिलाओं को टिकट बांटा था लेकिन यह कुल सीटों का मात्र 12 प्रतिशत ही था।

सपा और कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव लड़ी थीं इनमें 114 सीटों में से 12 पर कांग्रेस ने और सपा ने मात्र 34 महिलाओं को ही मैदान में उतारा था। बसपा ने 21 महिलाओं को ही टिकट दिया था। इस तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने मिलाकर मात्र 96 महिलाओं को चुनाव में उतारा था।

वोट देने में आगे, टिकट पाने में पीछे

यूपी के कुल 14.6 करोड़ वोटरों में 6.70 करोड़ वोटर महिलाएं हैं। कांग्रेस का दावं इन्हीं पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव का आकलन करें तो यूपी में एक तिहाई से ज्यादा जिलों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज्यादा था। इसके बावजूद राजनीतिक दलों से टिकट पाने में महिलाएं पीछे रहीं हैं।

अन्य दलों में बेचैनी

कांग्रेस द्वारा 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा पर विभिन्न दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस का यह दांव अन्य दलों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर राजनीतिक ताकत की बड़ी लकीर खींच दी है। यूपी की जातीय गणित में दमखम रखने वाले सियासी दल इसका राजनीतिक तापमान नापने में जुट गए हैं और इसकी काट के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं।

40 प्रतिशत टिकट की घोषणा महज नाटक : मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देने की घोषणा को चुनावी नाटकबाजी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है और उनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित व महिलाओं की याद नहीं आती है। पर अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह इनको महिलाओं की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्वभाव है 'कहना कुछ व करना कुछ' जो इनकी नीयत व नीति पर प्रश्नचिन्ह खड़े करता है।

कांग्रेस का है यह चुनावी हथकंडा : रीता बहुगुणा

महिलाओं को 40 फीसदी टिकट दिए जाने संबंधी प्रियंका गांधी की घोषणा को भाजपा ने चुनावी हथकंडा बताया है। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि 40 प्रतिशत टिकट देने की बात कांग्रेस उस यूपी में कर रही है जहां उसे पांच सीटे भी नहीं मिलेंगी। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां कितने सीटें दी।

माफिया मांग रहे माफी : मोदी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज योगी सरकार में माफिया माफी मांग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दर्द माफियावादियों को हो रहा है। इससे पहले की सरकारों में माफिया को खुली छूट थी, खुली लूट की इजाजत थी।

टी.बी. सिंह

भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीकों के सहारे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर सियासी समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया।

अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लोकार्पण व राजकीय मेडिकल कालेज के शिलान्यास के साथ ही इस शुअवसर पर उन्होंने योगी सरकार के काम और विपक्ष की नाकामियां गिनाकर आसन्न विधानसभा चुनाव में शानदार 'लैंडिंग' के लिए 'रनवे' भी तैयार करने का काम किया है। उन्होंने

छह मीटर लंबा चीवर दान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचकर शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा में सिर कर लेटे भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की और छह मीटर लंबा चीवर दान किया।

उल्लेखनीय है कि चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। मोदी ने कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज सहित 345 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 180 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

सियासत के तीर छोड़ते हुए पीएम मोदी ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोगों की पहचान समाजवादी की नहीं परिवारवादी की बन गई है। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का हित भूल गए। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोहिया कहते थे कर्म को करुणा से जोड़ों। लेकिन पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों और अपराधों से जोड़ा। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी हर अभियान में अग्रणी है।

योगी व उनकी टीम उन भू माफियाओं को ध्वस्त कर रही है जो पिछड़ो, गरीबों, दलितों और वंचितों की जमीन पर बुरी नजर डाल रहे थे। पिछली सपा सरकार को माफिया व परिवारवाद के सहारे घेरने के साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गए यूपी सरकार के कार्यों का उल्लेख कर अप्रत्यक्षतौर पर कांग्रेस को भी आईना दिखाया। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए नरेन्द्र मोदी ने पूर्वांचल की 160 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा ही गरीबों के लिए कल्याण करने को समर्पित है। सरोकारों के सहारे देश-दुनिया में रहने वाले बौद्ध मतालंबियों के साथ अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों में बड़ी संख्या में मौजूद भगवान बुद्ध को मानने वालों से भावनात्मक नाता जोड़ते हुए यह समझाने की भरपूर कोशिश की कि सिर्फ भाजपा की सरकारें ही उनके हितों को सम्मान दे सकती हैं। इसीलिए उन्होंने बार-बार न सिर्फ यह बतलाने की कोशिश की कि केन्द्र में उनकी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बौद्धों की आस्था से जुड़े स्थानों को गौरव, सम्मान तथा दुनिया से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किस तरह से तेजी से काम किए गए हैं। जबकि पहले की सरकारों ने किस तरह बौद्ध की नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक स्थलों की अनदेखी और उपेक्षा की। धार्मिक व तीर्थ सीलों का एक-एक का नाम लेकर भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देने का प्रयास किया। इसी के साथ आगरा व पीलीभीत के गुरुद्वारा से जुड़े गुरु गोविन्द सिंह साहब के शौर्य का जिक्र करते हुए सिक्ख समुदाय को संदेश दिया ही साथ ही लखीमपुरखीरी मे हुई घटना को लेकर आहत समाज पर मरहम लगाने का प्रयास किया।

उन्होंने इस मौके पर सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास के साथ एक नया शब्द 'सबका प्रयास' जोड़ते हुए सबको समग्र विकास के प्रयासों से जोड़ने की कोशिश की।

कुशीनगर के बरवा फार्म पर प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार की भूरि भूरि सराहना करते हुए कहा कि योगी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में यूपी देश को राह दिखाने वाला राज्य बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोनाकाल में देश ने इसे महसूस किया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पग-पग पर तीर्थ और कण-कण में ऊर्जा है। देश में सर्वाधिक वैक्सीन यूपी में लग रही है। कुपोषण की लड़ाई में यूपी की भूमिका अहम है। शौचालय, मकान से लेकर रसोई तक का महिलाओं को लाभ मिला है। पीएम स्वामित्व योजना से गांव की समृद्धि का द्वार खुलने वाला है।

चार साल में तैयार होंगे 200 एयरपोर्ट : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उदघाटन करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने उन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी पर अधिक जोर दिया है जहां के बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं था। सरकार की कोशिश है कि आने वाले चार साल में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी-प्लेन के लिए वाटरपोर्ट भी तैयार किए जाएं। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि देश का सिविल एविएशन सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक हजार नए प्लेन जुड़ेगे। इससे निचले और मध्यम स्तर के लोग भी प्लेन में सफर कर सकेंगे।

उन्होंने एयरपोर्ट का लोकार्पण करने के बाद तभागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण सीली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरूआत की। पहली फ्लाइट श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत 900 से अधिक हवाई रूट स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 350 पर हवाई सेवा शुरू हो गई है। 50 से अधिक एयरपोर्ट चालू हैं।

हाल ही में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी लांच किया गया है। इससे गवर्नेंस में सुधार आएगा ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की क्षमता को बढ़ाएं। देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल में एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम उठाया गया है। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई उर्जा देगा। ऐसा ही एक बड़ा सुधार डिफेंस एयर स्पेस को सिविल यूज के लिए खोलने से जुड़ा है।

तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 से 2014 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थे। अब लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पर्यटन के क्षेत्र में ढेरों संभावनाएं और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

इस अवसर पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री के जिन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू कराया। भगवान बुद्ध से जुड़े सभी देशों को उनकी परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य किया।

उन्होंने कहा कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में नौवें एयरपोर्ट के रूप में अस्तित्व में आया है। आज यूपी के हवाई अड्डों से 75 प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा है। इस समय प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर काम हो रहा है। नोएडा और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कार्य प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आठ एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 2017 के पहले ऐसे केवल दो एयरपोर्ट थे। एक लखनऊ और दूसरा वाराणसी में।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रदेश का तीसरा क्रियाशील और सबसे लंबे रन वे वाला एयरपोर्ट है। 45 मीटर की चौडाई में इसके रनवे की लंबाई 3200 मीटर है। 260 करोड़ रूपये की लागत से 589 एकड़ में बने इस एयरपोर्ट के एप्रन पर एक साथ चार हवाई जहाज खड़े किए जा सकते हैं। ❑

यूपी में हवाई सेवाएं

क्रियाशील	यहां भी योजना	ये कतार में	
लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, हिंडन, कानपुर, बरेली।	चित्रकूट, सोनभद्र, सहारनपुर, झांसी, मेरठ, ललितपुर में भी शुरू करने की योजना।	अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद।	लखनऊ और वाराणसी से उडान की सुविधा। अब कुशीनगर शुरू। अयोध्या 2022, जेवर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट होगा।

गौरीगंज विधायक का इस्तीफा

लाल मोहम्मद राईन
9415664060

अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बड़ा कदम उठाते हुए न केवल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा ही दिया बल्कि अपने समर्थकों के साथ अनशन पर भी बैठ गए। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके क्षेत्र की दो जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं होने से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया। राकेश प्रताप सिंह सपा से विधायक हैं। हालांकि जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। कार्यकाल समाप्त होने में महज चार माह शेष हैं। इस्तीफा देकर सड़क की मांग करना चौंकाने वाला है।

उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर जाकर मिलने के बाद सौंप दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे पत्र में आरोप लगाया कि वह वर्तमान शासन में जनता की समस्याओं का निस्तारण करने में सक्षम नहीं हैं ऐसे में वो इस्तीफा दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वह पिछले तीन साल से यह मामला सदन से लेकर शासन तक उठाते रहे हैं। विगत 2 अक्टूबर को जिलाधिकारी को पत्र देकर यह भी बताया था कि 31 अक्टूबर तक सड़क नहीं बनने पर वह विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होना दुःखद है। ऐसी स्थिति में विधानसभा सदस्य बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राकेश सिंह गंभीरता से अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सदन व उसके बाद उठाते रहे हैं। जहां तक उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की बात है तो वह विधानसभा नियमावली के हिसाब से निर्णय लेंगे।

उल्लेखनीय है कि राकेश प्रताप सिंह ने 31 अक्टूबर तक सड़क के निर्माण कार्य न शुरू कराने पर इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में राकेश का कहना है कि 25 फरवरी 2021 को सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनके क्षेत्र के दो मार्गों का निर्माण 3 माह में पूरा हो जाएगा। जबकि अभी तक उस पर काम नहीं शुरू हो सका है।

14.65 किलोमीटर की सड़क के लिए इस्तीफा दे चुके विधायक राकेश सिंह 19 महीने से लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में अब जबकि विधानसभा चुनाव अत्यंत निकट है तो उनके इस्तीफे को कुछ लोग सियासी भी मान रहे हैं।

जहां तक दो सड़कों की बात है तो लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कादूनाला से निकल कर थौरी मार्ग व मुसाफिर खाना से निकलकर पारा बाजार को जोड़ने वाली दोनों सड़कों का निर्माण वर्ष 2016 में हुआ था। 9 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण करीब 3.80 करोड़ रुपये की लागत से यूनिक कांस्ट्रक्शन कंपनी व 5.65 किलोमीटर लंबे मुसाफिर खाना-पारा संपर्क मार्ग का निर्माण करीब 4.28 करोड़ रुपये से मेसर्स राज कांस्ट्रक्शन्स कंपनी ने कराया था।

2016 में सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू हो गया था। इसके लिए मिट्टी और अन्य सामानों की ढुलाई के चलते भारी वाहनों के आवागमन से उक्त दोनों सड़के क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के लिए विधायक राकेश सिंह से गुहार लगाई। उन्होंने इस मामले को विधानसभा की प्राकलन समिति के समक्ष रखा। समिति ने मौके का निरीक्षण भी किया। लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। वैसे इस संदर्भ में डीएम का कहना है कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।

बावजूद इसके अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक ने इस्तीफा देने के बाद हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष अपने समर्थकों के साथ अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है कि सड़क के निर्माण होने तक उनका अनशन जारी रहेगा।

अयोध्या से
मुकेश श्रीवास्तव
7985825195

राम की नगरी अयोध्या में पांचवें दीपोत्सव ने एक अलग ही छटा बिखेरी। अयोध्या दीपोत्सव 2021 में साढ़े नौ लाख मिट्टी के दिये जलाकर लगातार चौथी बार गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकार्ड बनाया। साथ ही लोगों को यह भी याद दिलाया कि 31 साल पहले जहां रामभक्तों पर गोलियां चलाई जाती थीं, वहीं आज फूलों की वर्षा हो रही है। रिकॉर्ड दीपोत्सव से जहां राम नगरी सोने सी दमक उठी तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीयों के बहाने 2022 की विधानसभा चुनाव में भाजपा की भावी रणनीति का संकेत देते हुए विपक्षियों पर जोरदार निशाना साधा।

उन्होंने प्रतीकों के सहारे विपक्षियों को निशाने पर साधते हुए लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि आगामी चुनाव में भाजपा क्यों जरूरी है। जिस तरह जिस रंग और अंदाज में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की आस्था, समर्पण व संकल्प का संदेश दिया उसके चलते विपक्ष के समक्ष समस्याएं और सवाल खड़ा किया। केवल यही नहीं उन्होंने दीपोत्सव के दौरान गरीबों के कल्याणार्थ बड़ा ऐलान किया उससे भी विरोधियों की मुश्किलें ही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक उनकी सरकार केवल खाद्यान्न के नाम पर गेहूं और चावल ही नहीं देगी बल्कि चीनी, दाल, खाद्य तेल और नमक भी मुफ्त में देगी।

दिव्य और भव्य दीपोत्सव के मनोरम व मनोहारी मंच से मुख्यमंत्री की घोषणा से हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय जय-जयकार के नारे करने लगी। उन्होंने जिस तरह गरीबों की समस्याओं के समाधान को हिंदुत्व की आस्था से जुड़े स्थलों के विकास से सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों से जोड़ा। उससे भी यह साफ हो गया कि 2022 की चुनावी चौसर पर भाजपा की तरफ से हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को चौतरफा घेराबंदी की पूरी तैयारी है। एक तरह से योगी ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि भाजपा की 2022 के चुनाव में

इस तरह बिना नाम लिए जहां उन्होंने सपा पर कटाक्ष किया तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी 70 साल के कांग्रेसी शासन को रामद्रोही ठहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। योगी की तरह उन्होंने ने भी कांग्रेस, सपा और बसपा को रामभक्तों का सबसे बड़ा विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा।

छोटी दीपावली पर दीपोत्सव की व्यापकता और भव्यता से जहां अयोध्या राममय नजर आ रही थी तो वहीं योगी सरकार के सभी मंत्रिगण भाव-विभोर थे। राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्य किस तरह आस्था से अभिभूत थे इसका नजारा यह था कि न केवल योगी के मंत्रिगण बल्कि वह खुद अन्य अतिथियों के साथ मंच के नीचे बैठे थे। जबकि वहीं मंच पर प्रभु श्रीराम माता जानकी भ्राता लक्ष्मण साथ ही हनुमान के स्वरूप ने राज दरबार सजाकर त्रेतायुग की याद दिला दी। खुद मुख्यमंत्री ने स्वरूपों की अगवानी की। पूरे अयोध्या में राम की झांकी सजी और छतों से राम दल पर फूलों की वर्षा की गई। चारों दिशाओं में राम का नाम गूंजता रहा।

छोटी दिवाली पर आयोजित पांचवें दीपोत्सव में इस बार और रिकॉर्ड बना। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 से ही अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा का श्रीगणेश कर रखा है। ❑

दीपोत्सव का रिकॉर्ड

वर्ष 2017 में एक लाख 87 हजार दो सौ दीयों का रिकार्ड कायम हुआ। पुनः वर्ष 2018 में तीन लाख 11 हजार चार व वर्ष 2019 में चार लाख चार हजार व वर्ष 2020 में 6 लाख 6 हजार दीयों को जलाने का नवीन रिकार्ड कायम किया गया था।

इस बार राम की पैड़ी पर जलाए गए दीयों का नया रिकार्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह संख्या 9 लाख 54 हजार आंकी गई। पिछली बार राम की पैड़ी के अलावा घाटों पर दीये जले थे। इस बार इसका दायरा बढ़ाकर अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिर अन्य सार्वजनिक स्थल व मठ भी शामिल थे।

साढ़े नौ लाख दीयों को जलाने के लिए तकरीबन 36 हजार लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया। इन दीयों को जलाने के लिए लगभग 12 हजार कार्यकर्ताओं की टोली थी।

लोकार्पण व शिलान्यास

दीपोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्यावासियों को कुल 678.61 करोड़ रुपये की 51 परियोजनाओं की सौगात भी दी। इनमें 122.50 करोड़ के 27 कार्यों का लोकार्पण और 556.11 करोड़ के 24 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इनमें प्रमुख तौर पर लोक निर्माण विभाग से कराए जाने वाले 114.96 करोड़ की लागत से 5.50 किमी अयोध्या-गोसाईगंज बाईपास निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया।

धर्म, ध्रुवीकरण और जनकल्याण के लाइन पर चलते हुए वह जनता के बीच जाएगी।

उन्होंने कब्रिस्तान से भी भाजपा के एजेंडे को धार दी। कब्रिस्तान की चहारदीवारी और मंदिरों के निर्माण के खर्च में फर्क के बहाने अपनी मंशा भी साफ कर दी। इसके चलते उन्होंने यह संदेश भी दिया कि भाजपा सरकार धर्म और संस्कृति के उत्थान के प्रति समर्पित है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको यह तय करना है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल और खर्च करने वाली सरकार चाहिए या मठ, मंदिरों पर खर्च करने की प्राथमिकता देने वाली सरकार चाहिए। पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखे मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव 2021 का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की शक्ति है कि जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को राम भक्तों और कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था आज वे ही जनता के सामने नतमस्तक हैं।

उप चुनाव का रहा मिला-जुला नतीजा

मिली-जुली खुशी

आयुष सिंह

देश के 13 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में हुए उप चुनाव के नतीजे किसी एक दल के लिए खुशी नहीं ला सके। तीन लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उप चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नतीजे मिले जुले रहे। यानी नतीजा दोनों पार्टियों के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम वाले साबित हुए।

हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस ने सभी सीटें जीतकर जहां भाजपा को झटका दिया है तो वहीं मध्य प्रदेश, असम और नार्थ ईस्ट के राज्यों में भाजपा ने खुद को और मजबूत किया है। वैसे हिमाचल को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में सत्तारूढ़ दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई राज्यों में यह नतीजे भावी राजनीति को प्रभावी कर सकते हैं। खासकर जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। वैसे कई राज्यों में उप चुनाव के नतीजे स्वाभाविक लगते हैं।

हिमाचल प्रदेश

उप चुनावों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे हिमाचल प्रदेश से आए हैं। यहां भाजपा का कांग्रेस ने सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा को हराते हुए एक लोकसभा सीट (मंडी) और तीनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। उसने लोकसभा व विधानसभा की एक-एक सीट भाजपा से छीनी है। जबकि राज्य में भाजपा की सरकार है। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है उसे ऐसी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए हिमाचल की हार जीत को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। वैसे हिमाचल में चुनाव होने में अभी देर है। वहां ठीक एक साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।

हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने भाजपा के कुशल चंद्र ठाकुर को 7,490 वोटों से हराया।

फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की भवानी सिंह पठानिया ने भाजपा के बलदेव ठाकुर को हराया। अरकी सीट पर कांग्रेस के संजय सिंह तो जुब्बलकोट खाई से रोहित ठाकुर जीते।

राजस्थान

राजस्थान में भी कांग्रेस ने दोनों सीटें जीतकर यहां भी भाजपा को झटका दिया है। इनमें से एक सीट पहले भाजपा के पास थी। यहां कांग्रेस की गहलौत सरकार भले ही गुटबाजी से त्रस्त है लेकिन मुख्यमंत्री गहलौत ने दोनों सीटें जीतकर अपनी साख को बचाने में सफलता हासिल कर ली है। बल्लभ नगर में कांग्रेस की प्रीती गजेन्द्र सिंह शेखावत विजयी रहीं वहीं धारियावाड़ सीट पर कांग्रेस के नागराज ने निर्दलीय थावर चंद्र को शिकस्त दी।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा सीटें पर टीएमसी का क्लीन स्वीप रहा। तो वहीं भाजपा की तीन सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। जिससे पार्टी के प्रदर्शन पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।

इस जीत से गदगद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट किया, ‘ चारो उम्मीदवारों को जीत की बधाई’।

असम

असम में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। यहां उसने सहयोगी पार्टियों के साथ सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की। यहां पहले एक भी सीट पर भाजपा नहीं थी।

मध्य प्रदेश

यहां भाजपा अपनी थोड़ी साख बचा पाने में सफल रही। यहां पृथ्वीपुर और जोबट सीट वह कांग्रेस से बचा ले गई लेकिन रैनगांव सीट वह कांग्रेस के हाथों हार गई।

बिहार

बिहार में जमानत पर आए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का प्रभाव काम नहीं आया। यहां की दोनों सीटें जेडीयू के खाते में गईं। यहां जेडीयू के राजीव कुमार सिंह जीते।

दादरा

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से सात बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पत्नी कलावती डेलकर 51 हजार वोटों से जीतीं।

मोहन डेलकर की मुंबई के होटल में संदिग्ध हालातों में मौत के बाद उप चुनाव हुए थे। उनकी पत्नी कलावती शिवसेना के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरीं थीं। उन्होंने भाजपा के महेश गावित हो हराया। दादरा में शिवसेना की यह पहली जीत है।

इसी तरह हरियाणा की एलनाबाद सीट पर आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला ने भाजपा के गोविंद कांडा को हराया।

कर्नाटक में भाजपा एक सीट हारी तो एक पर कांग्रेस को हराया। जबकि महाराष्ट्र की देगलूर सीट पर भाजपा के साबडे सुभाष कांग्रेस के अंतापुरकर जितिश से हार गए। आंध्र की वाडबेल सीट पर भी भाजपा हारी। ❑

भाजपा के चुनाव अभियान की शुरूआत

'फिर एक बार, भाजपा 300 पार'

• वीरेन्द्र शुक्ल

पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में अमित शाह का अहम रोल था। इस बार भी उन्होंने फिर एक बार, भाजपा 300 पार का नारा देते हुए भाजपा के चुनाव अभियान की शुरूआत कर दी है।

इसके लिए उन्होंने भाजपा के वृहद सदस्यता अभियान, 'मेरा परिवार भाजपा परिवार' के अभियान की भी शुरूआत कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता हथियाने का जरिया चुनाव नहीं है। यह मौका अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। विपक्षी दलों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का माध्यम है जबकि भाजपा के लिए चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव और लोकसंपर्क का जरिया है। यही वजह है कि भाजपा चुनाव से पहले सदस्यता अभियान की शुरूआत कर रही है। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान का श्रीगणेश भी इसी

जो कहा कर दिखाया : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा ने देश व प्रदेश में शासन कर साबित कर दिया है कि वह जो कहती है, करती है।

भाजपा ने गरीब कल्याण योजनाओं से लेकर एकता और अखंडता के साथ 'एक भारत शेष भारत' की परिकल्पना को साकार किया है।

जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा देश की सत्ता सौंपी तो उन्होंने अयोध्या विवाद को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2000 के बाद शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तक पहुंचाया, साथ ही भारतीयता के मूल्यों की पुनर्स्थापना भी की।

सदस्यता अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं, गरीबों, दलितों व पिछड़ो को पार्टी से जोड़ा जाएगा और पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में चलेगा।

भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने अपने इस दौरे में न केवल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की ही बात की बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी फोकस रखा। उनका कहना है कि 2024 में नरेन्द्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वर्ष 2022 में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है।

गृहमंत्री अमित शाह ने एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की तो वहीं उनकी उपलब्धियों को भी बताया। इसके साथ ही सपा, बसपा व कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप उक्त तीनों पार्टियों पर यूपी को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि सपा व बसपा राज में हर जिले में दो तीन माफिया-बाहुबली हुआ करते थे लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में आज दूरबीन से देखने पर भी माफिया नहीं दिखते। पश्चिमी यूपी के पलायन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सपा शासन में यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति देखकर खून खौलता था। पश्चिमी यूपी में कैराना से पलायन शुरू हुआ था तब भी लखनऊ में बैठे सत्ताधीशों की नींद नहीं टूटी थी। अब योगी सरकार में पलायन कराने वाले खुद पलायन कर रहे हैं।

शाह ने वैसे तो कांग्रेस और बसपा की खिंचाई की लेकिन सपा पर सर्वाधिक निशाना साधा। ज्यादातर हमलों का फोकस पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर ही रखा। उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी सपा ही है। ❑

गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां

गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यूपी को अपनी पहचान वापस दिलाने और देश का सबसे प्रमुख राज्य बनाने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया। भाजपा ने अपने कार्यों से यह साबित किया है कि सरकार परिवार के लिए नहीं बल्कि सूबे के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होती है।

उन्होंने कहा कि 2017 में जब भाजपा को सत्ता मिली थी तब उत्तर प्रदेश देश में सातवें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आज साढ़े चार साल में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ से बढ़कर 21 लाख 31 हजार करोड़ की हो गई है। बेरोजगारी की दर 18 से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई है। पहले 12 मेडिकल कालेज थे अब 30 बन गए हैं। 2022 के पहले 40 का वादा पूरा करेंगे।

शाह ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में हुए कानून व्यवस्था में सुधार को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों, प्रदेश महा मंत्रियों, चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी और संगठन प्रभारियों की बैठक में फीडबैक लिया।

उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान के शुरुआत के साथ ही कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की दिशा भी समझा दी। उन्होंने साफ किया कि आगामी चुनाव में भाजपा यूपी के आत्म सम्मान और पहचान के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। इन पर बचे कामों को पूरा करने के लिए जनता से समर्थन मांगेगी। लोगों को भाजपा और गैर भाजपा की सरकारों का फर्क समझाकर उनके दिल में बात बैठाने का प्रयत्न होगा कि गैर भाजपा सरकारों के द्वारा प्रदेश की पहचान से हुए खिलवाड़ पर विराम लगाकर योगी सरकार ने किस तरह प्रदेश के आत्मसम्मान और पहचान की वापसी के लिए काम किया। पर अभी तमाम काम बाकी हैं। जिसके लिए 2022 में भाजपा की सरकार जरूरी है।

महोबा के पान को मिला जीवनदान

GI टैग मिलने से मिलेगी पहचान

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का देशावरी पान भले ही अपने स्वाद और खुशबू के लिए देशभर में प्रसिद्ध और जाना जाता रहा है। लेकिन यहां पान किसानों का हाल बेहाल ही देखने में आता था।

बदहाल पान कारोबार को अब जीआई टैग मिलने से न केवल पान व्यापार को नई पहचान मिलने की ही आशा जगी है बल्कि किसानों की तकदीर बदलने का रास्ता भी साफ हो गया है क्योंकि लंबे समय से जीआई टैग दिए जाने की मांग महोबा के पान किसान कर रहे थे। लेकिन अपनी मांग के अनसूनी होने के चलते वे निराश और हताश हो चले थे। इसके चलते पैदावार में भी कमी होती चली आ रही थी।

वैसे पान की खेती देश के अन्य कई राज्यों में होती है। मगर महोबा के देशावरी पान की अलग ही पहचान और स्वाद थी। यहां का पान खाड़ी के देशों में भी पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में तो यहां के पान की बहुत मांग है। लेकिन प्रोत्साहन और संरक्षण न मिलने से यहां का पान व्यापार चौपट होने की कगार पर जा पहुंचा था।

उल्लेखनीय है कि महज पांच दशक पहले महोबा में पान की खेती 300 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में होती थी। आल्हा ऊदल के बाद यहां के देशावरी पान ने महोबा को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीयस्तर पर पहचान दिलाने का काम किया था। लेकिन गुटखा संस्कृति की चलन और पान किसानों को कोई सुरक्षा व संरक्षण न मिलने के चलते पान की खेती उजड़ते-उजड़ते 20 एकड़ तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब जी आई टेग मिलने से बदहाल पान करोबार के दिन बहुरने की उम्मीद जग उठी है।

जहां तक महोबा में पान की खेती की बात है तो चंदेल शासकों को यहां के पान किसानों को बरेजा लगाने के लिए भूमि और मदद देकर बड़े पैमाने पर पान की खेती प्रारंभ कराई थी। लेकिन धीरे-धीरे उपेक्षा के चलते यहां का पान और पान किसान दोनों ही बदहाली के अंधेरे में गुम होने लगे। इसको देखते हुए लगभग आठ साल पहले 2014 में महोबा तत्कालीन जिलाधिकारी डा. काजल ने जीआई टेग (जियोग्राफिगल इंडीकेशन रजिस्ट्री) के लिए महोबा के

क्या है GI टैग?

जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 'जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आफ गुड्स' लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग चाय इसी कानून के तहत संरक्षित हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स का काम उस खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर-कानूनी प्रयोग को रोकना है।

किसको मिलता है : किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है. यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है। इसके साथ ही यह भी तय किए जाना जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उस वस्तु की पैदावार में कितना हाथ है। कई बार किसी खास वस्तु की पैदावार एक विशेष स्थान पर ही संभव होती है। इसके लिए वहां की जलवायु से लेकर उसे आखिरी स्वरूप देने वाले कारीगरों तक का हाथ होता है।

भारत में जीआई टैग्स किसी खास फसल, प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिए जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला-जुला जीआई टैग दिया जाए। यह बासमती चावल के साथ हुआ है। बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है।

देशावरी पान के लिए चौरसिया समाज सेवा समिति के माध्यम से पान किसानों से आवेदन करवाया था। उनके बाद इस पद पर आए दूसरे जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने भी जीआई टेग के लिए प्रयास किया तो शासन ने जीआई टेग के लिए पान को शामिल कर और जिलों से अपत्तियां मांगी थीं। देखा जाए तो जीआई टेग भारत में किसी खास फसल और तैयार उत्पाद को दिया जाता है। यह एक प्रकार का लेवल होता है जिससे प्रोडक्ट की भौतिक पहचान होती है। इस टेग को जारी करने के पहले सामान की गुणवत्ता व पैदावार की जांच की जाती है। भारत में पहला जीआई टेग दार्जलिंग की चाय को मिला था। भारत में कुछ समय पहले तक 272 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका था।

अब जीआई टेग मिलने पर यहां के किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। किसान अब फिर से पान की खेती के प्रति रूचि दिखाएंगे यह तय है। यहां के पान किसानों को न केवल जीआई टेग ही मिला है बल्कि लंबे समय से पान की खेती को फसल बीमा के दायरे में लाने की मांग को भी प्रदेश सरकार ने मान लिया है। इस तरह महोबा जिले के पान किसानों को बहुत जल्द दोहरी खुशी मिली है। ❑

लग गए 100 करोड़ से ज्यादा टीके

कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने 100 करोड़ वैक्सीन की डोज से एक माइलस्टोन हासिल कर लिया। देश को इस एतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचने में 279 दिन लगे। देश और दुनिया ने भारत के इस मुकाम तक पहुंचने पर शुभकामनाएं दी हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत में टीकाकरण की शुरूआत इसी साल 16 जनवरी को हुई थी। शुरूआत में तो वैक्सीन की डोज लेने वालों की कमी के चलते टीकाकरण अभियान मंथर गति से चला था लेकिन बाद में इसने रफ्तार पकड़ ली। 100 करोड़ टीकों का कोरोना कवच के पार तक पहुंचने वाला चीन के बाद भारत दूसरा देश है। देश में अब तक 71.09 करोड़ वयस्क आबादी को टीके की एक खुराक और करीब 29. 52 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। अब तो यह संख्या और आंकड़ा और भी ज्यादा हो चुका है।

100 करोड़वां टीका नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वाराणसी के दिव्यांग अरूण राय को लगा। इस विशिष्ट मौके के गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बने। क्योंकि वह उस समय वहां मौजूद थे। इस अवसर पर अरूण ने कहा कि उनके लिए यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने टीका लगवाने वाले अरूण से बातचीत भी की और उससे गाना भी सुना।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लयू एच ओ) ने ट्वीट किया, 'भारत में 100 करोड़ डोज पूरे होने पर पीएम मोदी, वैज्ञानिकों, स्वास्थ कर्मियों और भारत के नागरिकों को बधाई।' वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीया ने लालकिले से एक गीत और फिल्म जारी की। इसमें टीकाकरण के सफर को दर्शाया गया। किले पर देश का सबसे बड़ा खादी तिरंगा भी लहराया गया। जिसका वजन करीब 1400 किलो है। इस तिरंगे की लंबाई 225 फुट और चौडाई 150 फुट है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के इस बड़े मुकाम तक पहुंचने पर कहा कि पिछले 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए देश के पास अब टीकों की 100 करोड़ खुराकों का मजबूत 'सुरक्षा कवच' है। यह भारत के हर नागरिक की उपलब्धि है। उन्होंने इस सफलता के लिए टीका बनाने वाली सभी कंपनियों, टीकों के परिवहन में शामिल कर्मियों और टीका लगाने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के प्रति आभार प्रकट किया।

जिन नौ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी वयस्कों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है ये हैं अंडमान नीकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षदीप, सिक्किम, उत्तराखंड व दादरा नागर हवेली। इस क्रम में सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी वयस्कों को 31 दिसंबर तक टीका लग जाए। जबकि बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

विगत 16 जनवरी से प्रारंभ टीकाकरण के अंतर्गत 12 जून तक 25 करोड़ लोगों को खुराक दी जा चुकी थी जबकि 50 करोड़ को आंकड़ा 6 अगस्त को और 75 करोड़ का आंकड़ा 13 सितंबर तक का था। जबकि 100 करोड़ के अहम पड़ाव पर देश 21 अक्टूबर को पहुंच गया। ❑

यूपी में सबसे ज्यादा टीके लगे

भारत को 100 करोड़ कोरोना टीका लगाने वाला विश्व का दूसरा देश बनाने में यूपी की अहम भूमिका है। इस टीकाकरण में 12 प्रतिशत भागीदारी यूपी की है। इसमें कोरोना टीके के पहली और दूसरी दोनों डोज लगवाने वाले शामिल हैं। यूपी के नाम सर्वाधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाने का रिकार्ड भी दर्ज है।

कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय सिर्फ कोविड प्रोटोकाल का पालन और टीकाकरण ही था। ऐसे में देश में तेजी से टीकाकरण का महाभियान शुरु हुआ। जिसमें यूपी ने भी तेजी से वैक्सीनेशन शुरु किया। उसी का नतीजा है कि देश में सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद प्रदेश में कोरोना लगभग काबू में है।

कोविड पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार 21 अक्टूबर तक यूपी में पहली डोज लेने वालों की संख्या 9 करोड़ 43 लाख, 10 हजार 6 सौ बहत्तर थी। वहीं 6 करोड़ 43 लाख 98 हजार 03 टीके लगाकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था।

पहले ताश की तरह फेंटे जाते थे अफसर : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'लोक प्रशासन की सुदृढ़ीकरण' विषय पर आयोजित दो दिवसीय वर्कशॉप में कहा कि 2017 के पहले प्रशासनिक अधिकारी ताश के पत्तों के तरह फेंटे जाते थे। हमने अधिकारियों को उनका पूरा कार्यकाल और अवसर दिया, बशर्ते वे परफार्म कर रहे हों। हमने अच्छा काम करने वाले अफसरों को प्रोत्साहित किया और गलत करने वाले को दंडित भी किया।

उन्होंने कहा कि सरकार में आने पर जिस विभाग से बात करो वही मैनपावर की कमी की बात करता था। लगभग 10 सालों से भर्तियां पारदर्शिता के अभाव में फंसी थीं। सिविल पुलिस के आधे पद खाली थे। हमने इसके रोड़े हटाये और भर्तियों को आगे बढ़ाया। शासन की नियत साफ होनी चाहिए। जब आप ईमानदार ढंग से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो उसका फायदा मिलता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशासनिक पदों पर चयनित होकर आ रहे नए बैच के अफसरों में तेजी से पैसा कमाने की आदत है। वहीं अधिकारियों में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव भी है। वे काम को टालने और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने के आदी हैं। उन्हें सीखना होगा कि वे कैसे अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। उन्होंने क्षमता निर्माण आयोग का ध्यान प्रशासनिक अफसरों को इन कमजोरियों की ओर आकृष्ट कराते हुए कहा कि वह अधिकारियों को इन प्रवृत्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय करें।

2022 में रिटायर होंगे 31 आईएएस अफसर

अगले साल कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी सहित संजय अग्रवाल व देवाशीष के साथ ही कुल मिलाकर 31 आईएएस अफसर रिटायर हो जाएंगे।

योगी सरकार में अहम पदों पर अहम भूमिका निभा रहे कई आईएएस आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान या फिर नई सरकार बनने तक रिटायर हो जाएंगे।

इस संदर्भ में नियुक्ति विभाग ने वर्ष 2022 में रिटायर होने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। जनवरी में अपर मुख्य सचिव सिंचाई, जल संसाधन व परती भूमि विकास टी वेंकेटेश जनवरी में ही रिटायर हो जाएंगे। जनवरी में ही सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग देवाशीष पांडा व राजेन्द्र प्रसाद पांडेय भी रिटायर होने वालों में शामिल हैं। लगभग पूरे साल आईएएस अफसरों को रिटायर होना है। मार्च अगस्त अक्टूबर और दिसंबर में केवल एक-एक आईएएस रिटायर होंगे। जबकि अन्य महीनों में एक साथ कई अफसरों को रिटायर होना है।

ये अधिकारी होंगे रिटायर

जनवरी : देवाशीष पांडा, टी. वेंकटेश व राजेन्द्र प्रसाद पांडेय।

फरवरी : इफ्तेखारूददीन, अब्दुल शमद व अवनीश कुमार शर्मा।

मार्च : संजय अग्रवाल।

अप्रैल : आलोक सिन्हा, मुकुल सिंघल, एमवीएस रामारेड्डी, प्रभात कुमार सारंगी व शमीम अहमद खान।

मई : वीरेन्द्र कुमार सिंह वह डॉ. रमाशंकर मौर्या।

जून : राजेन्द्र प्रसाद, रविशंकर गुप्ता, भावना श्रीवास्तव व फेसल आफताब।

जुलाई : नरेन्द्र सिंह पटेल, अजय शंकर पांडेय, दिनेश कुमार सिंह-द्वितीय व डा. अशोक चंद्र।

अगस्त : अवनीश कुमार अवस्थी।

सितंबर : आलोक टंडन व डिंपल वर्मा।

अक्टूबर : डा. प्रदीप कुमार।

नवंबर : शालिनी प्रसाद, राजन शुक्ला, राधेश्याम मिश्रा व दीप चंद्र।

दिसंबर : श्रीकांत मिश्रा।

अफसरों को चुनाव ड्यूटी से पहले हलफनामा देना अनिवार्य

प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी अफसरों व कार्मिकों को एक घोषणा पत्र अनिवार्य होगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दाखिल किए जाने वाले इस घोषणा पत्र में इन अफसरों व कार्मिकों को अपनी तरफ से यह घोषित करना होगा कि उनका मौजूदा चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार से उनका किसी भी तरह का कोई भी निकट संबंध नहीं है। न ही वे राज्य या जिलास्तर पर किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं।

यही नहीं चुनाव आयोग के अनुसार इस घोषणा पत्र में चुनाव ड्यूटी से संबंधित लोगों को यह भी लिखना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है।

केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के तहत चुनाव के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात होने वाले पुलिस विभाग के आईजी, डीआईजी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आदि पर भी यह लागू होगा। आयोग ने इसी के साथ यह भी कहा है कि चुनाव ड्यिूटी में ऐसे सब इंस्पेक्टर नहीं लगाए जाएंगे जिनकी तैनाती उनके अपने गृह जनपद में है। ऐसे पुलिसकर्मी जो एक सब डिवीजन में पिछले चार वर्षों में से तीन साल से लगातार तैनात हैं उनको भी चुनाव ड्यूटी में नहीं

लगाया जाएगा।

चुनाव आयोग का यह भी निर्देश है कि सरकारी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रिंसिपल चुनाव ड्यिूटी में नहीं लगेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी यह मंशा कतई नहीं हैं कि चुनाव के नाम पर अफसरों व कर्मचारियों के तबादले किए जाएं। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि ऐसे किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ राजनीतिक पक्षपात के शिकायत जांच में सही पाई जाती है तो न केवल उसका तत्काल तबादला किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमोटी IAS अफसरों को मिला बैच

केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने चयन वर्ष 2020 में पीसीएस से आईएएस संवर्ग में चयनित सभी 25 अधिकारियों को बैच आवंटित कर दिया है। इनमें 10 को 2014 और 15 को 2015 बैच दिया गया है।

पिछले दिनों प्रदेश के 25 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति दी गई थी। चयन वर्ष 2020 में चयनित इन अधिकारियों में अशोक कुमार को वरिष्ठता में चयन वर्ष 2019 में चयनित 2014 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी गिरिजेश कुमार तयागी के ठीक बाद में स्थान मिला है। अशोक कुमार के बाद क्रमशः महेन्द्र प्रसाद, गौरव वर्मा, रजनीश चंद्रा, मनोज कुमार राय, निधि श्रीवास्तव, खेमपाल सिंह, संजय चौहान, सुनील कुमार चौधरी, व संतोष कुमार शर्मा को 2014 बैच एलाट किया गया है। इनके बाद सीधी भर्ती की 2015 बैच की सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि गुप्ता का स्थान है।

चयन वर्ष 2020 में 2015 बैच के लिए चयनित 15 प्रमोटी आईएएस अधिकारी 2015 बैच के सीधी भर्ती से सबसे जूनियन आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार चौहान से नीचे होंगे। अरविंद के बाद क्रमशः अरूण कुमार-द्वितीय, श्याम बहादुर सिंह, पवन कुमार गंगवार, बृजेश कुमार, हरिकेश चौरसिया, महेन्द्र सिंह, रवीन्द्र पाल सिंह, अनिल कुमार, वंदना त्रिपाठी, समीर, अर्चना गहरवार, कुमार विनीत, विशाल सिंह, धनंजय शुक्ला व कपिल सिंह को स्थान मिला है। कपिल सिंह के बाद 2016 बैच के सीधी भर्ती के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी शशांक त्रिपाठी का नाम है।।

आलोक सिन्हा बने आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष

कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा को यूपी आईएएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। विगत अप्रैल में दीपक त्रिवेदी की निधन के बाद से यह पद खाली चल रहा था।

1986 बैच के आईएएस ने अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि उनकी कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री से समय लेकर आईएएस वीक का आयोजन किया जा सके। बतौर अध्यक्ष वह चाहेंगे कि कॉडर की गरिमा को और बढाया जाए।

2022 में रिटायर होंगे 41 पीसीएस अधिकारी

अगले साल 41 पीसीएस अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। इनमें 14 मंडलों के अपर आयुक्त, कई जिलों के अपर जिलाधिकारी और शासनस्तर पर विशेष सचिव के रूप में कार्यरत अधिकारी शामिल हैं।

जनवरी में कुंज बिहारी अग्रवाल, सुरेन्द्र बहादुर यादव, अनिल कुमार मिश्रा, प्रमिल कुमार सिंह, राज नरायन पांडेय व विनय प्रकाश श्रीवास्तव सेवानिवृत्त होंगे। फरवरी में हरिशंकर यादव, रामकेश सिंह, शीतला प्रसाद, सीतारामस गुप्ता, मनीष कुमार नाहर, देवेन्द्र प्रताप मिश्र व रवि प्रकाश श्रीवास्तव सेवानिवृत्त होंगे। इसी तरह मार्च में शिव पूजन व सत्य प्रकाश सिंह-प्रथम और अप्रैल में इंद्र भूषण वर्मा, जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार मौर्य व अनिल कुमार सिंह-द्वितीय सेवानिवृत्त होंगे।

मई में अजय कुमार अवस्थी, विंध्यवासिनी व आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, जून में अनूप कुमार श्रीवास्तव, प्रेम प्रकाश पाल, गोरे लाल व गिरिजेश कुमार चौधरी और जुलाई में गंगाराम गुप्ता, रमेश प्रसाद मिश्र, अनिल कुमार त्रिपाठी, रामअरज व जय नरायन सेवानिवृत्त होंगे।

इसी तरह अगस्त में हरिशंकर, रतिभान व सुरेश चंद्र शर्मा, अक्टूबर में राजेंद्र प्रसाद-द्वितीय, नवंबर में राम अभिलाष व बिजेन्द्र द्विवेदी और दिसंबर में सर्वेश कुमार, अरूण कुमार शुक्ला, अजय कुमार श्रीवास्तव व सत्येन्द्र कुमार सिंह सेवानिवृत्त होंगे।

मामला विधानसभा चुनाव लड़ने का

अखिलेश की ना में योगी की हाँ

कुछ समय पहले यह चर्चा चली थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनका अब यह कहना है कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह सब पार्टी तय करेगी। वहीं वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव के संदर्भ में यह सलाह देना नहीं भूलते हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।

इस संदर्भ में अखिलेश यादव का कहना है कि यदि योगी आदित्यनाथ 2022 में विधान सभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें इस बार हार मिलने वाली है। भाजपा चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है।

इस प्रकरण पर योगी ने यह ऐलान कर दिया है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भाजपा जहां से चाहेगी वहीं से वे चुनाव लड़ेंगे। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर टिप्पणी की है। फिलहाल वह विधान परिषद के सदस्य हैं। इसे और स्पष्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव तो लड़ना ही है हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। भाजपा में टिकट का फैसला संसदीय बोर्ड में होता है। संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। विधानसभा चुनाव भी उस सीट से लड़ेंगे जहां से संसदीय बोर्ड फैसला करेगा।

उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा ने जो वादे किए थे वे सभी साढ़े चार साल में पूरे किए हैं। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर थे आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर बनी हुई है। साढ़े चार साल में कोई दंगा नहीं हुआ। दीपावली समेत सारे पर्व शांति पूर्वक संपन्न हुए। अयोध्या में दीपोत्सव का उत्तर प्रदेश का आयोजन वैश्विक मंच पर छा गया है। ❑

योगी के ऐलान के साथ अटकलें शुरू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चुनाव लड़ने के संकेत के साथ ही उनकी संभावित सीट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

उल्लेखनीय है कि यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव होगा। वैसे उनके अयोध्या से लड़ने की संभावना अधिक व्यक्त की जा रही है। भले ही विधानसभा का चुनाव वह पहली बार लड़ेंगे लेकिन वे अपने गृहनगर गोरखपुर से लगातार पांच बार लोकसभा का चुनाव लड़कर जीतते रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो भाजपा अपने सभी दिग्गजों को चुनाव में उतारने की योजना बना रही है। इसी योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी सहित सरकार के सभी शीर्ष मंत्रियों को चुनाव में प्रत्याशी बनाने पर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो सका है कि योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के रणनीतिकार उन्हें अयोध्या सीट से चुनाव में उतारने की सलाह दे रहे हैं। इसके पीछे ऐसा कहने वालों का तर्क है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पहले से वाराणसी है तो वहीं अयोध्या से योगी का विधानसभा क्षेत्र होने से पार्टी ज्यादा राजनीतिक फायदे में रहेगी। यद्यपि वह अयोध्या से चुनाव लड़ने का सवाल टाल गए। उनका कहना है कि पूरा प्रदेश अपना है। पार्टी जहां से भी चुनाव मैदान में उतारेगी। वहीं से वे लड़ेंगे।

पेगासस जासूसी की जांच होगी

जुलाई 2021 में द गार्जियन, द वाशिंगटन पोस्ट और द वायर सहित 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी संयुक्त जांच के आधार पर भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा फोन नंबर हैक किए जाने का दावा किया था। मीडिया संगठनों की जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल और फारबिडेन स्टोरीज को प्राप्त लगभग 50 हजार नामों और नंबरों पर आधारित थी। द वायर ने खुलासा किया था कि भारत में भी 10 फोन की फॉरेंसिक जांच करवाई गई। ये सभी या तो हैक हुए थे या इनकी हैकिंग का प्रयास किया गया था।

इनमें केन्द्र सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, तमाम वकील, कुछ जज और कारोबारी समेत 300 प्रतिष्ठित लोगों के नंबर भी शामिल हैं।

पेगासस का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत के अलावा अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी और यूएई शामिल हैं।

पेगासस जासूसी प्रकरण से सनसनी फैलनी स्वाभाविक थी। इसी के चलते विगत 22 जुलाई को एम.एल. शर्मा ने याचिका दाखिल कर अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग की थी। फिर 27 जुलाई को पत्रकार एन. राम और शशि कुमार भी इस मामले को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिसके चलते पांच अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि पेगासस जासूसी की जांच होगी। इसके लिए शीर्ष अदालत ने साइबर विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन कर आठ सप्ताह में जांच पूरी करने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर बच नहीं सकती।

पेगासस जासूसी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पेगासस जासूसी से जुड़े मामले में अदालत का काम मीडिया सूत्रों की सुरक्षा के महत्व के लिहाज से अहम है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. बी. रविन्द्रन इस कमेटी के काम काज की निगरानी करेंगे। वहीं रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग के अध्यक्ष संदीप ओबेराय निगरानी में उन्हें सहयोग देंगे। तीन सदस्यीय समिति में डा. नवीन कुमार चौधरी, डा. प्रबाहरन पी. और डा. अश्विन अनिल गुमास्ते शामिल हैं।

इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एन. बी. रमन, सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इसके साथ ने पीठ ने आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का केन्द्र का अनुरोध ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई पक्षपात के खिलाफ स्थापित सिद्धान्त के विरुद्ध होगी। वह 6 बाध्यकारी परिस्थितियों को देखते हुए समिति की नियुक्ति कर रही है। निजता के अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का आरोप है। जिसकी जांच की जरूरत है। ❑

क्या है पेगासस

इजरायली कंपनी एनएसओ का पेगासस स्पाईवेयर ' नेटवर्क इंजेक्शन' तकनीक के तहत किसी बेस ट्रांसमीटर स्टेशन (बीटीएस) के जरिए लोगों के फोन में सेंध लगाने में सक्षम हैं। बीटीएस उस फर्जी मोबाइल टावर को कहते हैं, जिसका निर्माण वैध सेलुलर टावर की नकल के तौर पर किया जाता है।

कितना खतरनाक

पेगासस फोन पर आने-जाने वाले हर कॉल का ब्योरा जुटाने की क्षमता रखता है। यह फोन में मौजूद मीडिया फाइल और दस्तावेजों के अलावा उस पर आने-जाने वाले एसएमएस, ईमेल और सोशल मीडिया मैसेज की भी जानकारी दे सकता है। पासवर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट, कलेंडर इवेंट आदि की जानकारी देने में भी सक्षम है।

गर्भगृह तक सूरज की किरण

2022 से शुरू हो सकता है स्तंभों का निर्माण।
2023 के अंत तक गर्भगृह के निर्माण की संभावना।

अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में अनेक खूबियों के साथ-साथ रामलला के गर्भगृह को सूर्य के किरणों से प्रकाशमान करने की भी तैयारी है। इसके चलते ओडिसा के कोणार्क मंदिर जैसी तकनीकी अपनाने पर विचार विमर्श जारी है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि भगवान राम के मंदिर में प्रत्येक रामनवमी पर गर्भगृह में सूर्य की किरणें रामलला को सुशोभित करें, ऐसे ही प्रस्ताव पर काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि राममंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और प्रत्येक रामनवमी पर गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा पर सूर्य की किरणे सीधे पड़े इसके लिए कुछ प्रारूपों (मॉडल) पर वैज्ञानिकों, खगोलशास्त्रियों और तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श जारी है।

राम मंदिर के निर्माण के दौरान भूगर्भीय, भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय संबंधी स्थितियों सहित कई बातों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भूगर्भीय वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश भूकंप संवेदी क्षेत्र में आता है। मंदिर परिसर के पास नदी क्षेत्र है। संपूर्ण इलाका हिमालयी क्षेत्र के दायरे में आता है। इस नाते वैज्ञानिकों व खगोलशास्त्रियों से भी इन तमाम विषयों पर परामर्श लिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ओडिसा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर में गर्भगृह के अंदर तक सूर्य किरणे पहुंचती हैं। वैसे ही अयोध्या के रामलला के मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की किरणें कैसे पहुंचे, इसको लेकर सभी तकनीकी पहलुओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर विचार जारी है। इस संदर्भ में मंदिर निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर एक समिति गठित की गई है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की सहित राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्थान के विशेषज्ञों एवं अन्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं।

इस समय अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मध्य नवंबर तक मंदिर के प्लिंथ के निर्माण का कार्य पूरा होने का लक्ष्य है। तत्पश्चात अप्रैल 2022 से प्लिंथ के उपर लगने वाले स्तम्भों का काम शुरू होगा। जहां तक प्लिंथ के निर्माण की बात है तो यह 400 इन टू 3 सौ फुट में है। इस पर 365 फुट लंबाई और 235 फुट चौड़ाई में 171 फुट ऊँचे मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर में एक संग्रहालय, अभिलेख कक्ष, अनुसंधान केन्द्र, सभागार, गौशाला, पर्यटन केन्द्र, प्रशासनिक प्रभवन, योग केन्द्र और अन्य सुविधाएं होंगी। कोशिश यह है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो जाए ताकि श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकें। इसके आगे मंदिर के विस्तार एवं भव्यता का अन्य निर्माण कार्य चलता रहेगा। अभी तक नींव का पहला चरण पूरा हो चुका है जब कि दूसरा चरण नवंबर के मध्य तक खत्म हो जाने की संभावना है।

जहां तक भव्य और विशाल राममंदिर के निर्माण की बात है तो पूर्व के नक्शे एवं मॉडल में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले दो मंजिलों का निर्माण होना था। लेकिन अब बदले स्वरुप में राम मंदिर तीन मंजिला होगा।

हेल्थ मंच

छिलके हैं सेहत का खजाना

आमतौर पर यह माना जाता है कि फल और सब्जियां स्वास्थ के लिए लाभप्रद होती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं हैं कि उनके छिलकों में कई तरह के पोषक तत्वों के होने से छिलके भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। छिलके भी सेहत को दुरुस्त रखने में उतने ही मददगार होते हैं जितने की फल और सब्जियां।

शोधों से पता चला है कि गहरे रंग के छिलकों में भरपूर गुणवत्ता होती है। दरअसल इनमें भरपूर मात्रा में कांसनट्रेटेड फाइटो कैल्सियम पाया जाता है। जिसके चलते अलग-अलग सब्जियों और फलों के छिलके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ-साथ आयरन, पोटैशियम, विटामिन, जिंक आदि से परिपूर्ण होते हैं।

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार कुछ फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्न हैं।

केले का छिलका दूर करे डिप्रेशन

केले के छिलके में फीलगुड हारमोन 'सेरोटोनिन' पाया जाता है। सेरोटोनिन ब्रेन केमिकल है। जो व्यक्ति के मूड को बेहतर बनाने का कार्य करता है। यह आपकी उदासी दूर करने के साथ-साथ तनाव कम करने में भी मददगार होता है।

केले के छिलके में ल्यूटिन एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। जो आंखों को आल्ट्रावायलेट किरणों से बचाकर मोतियाबिंद के खतरे से बचाने का काम करता है। इसके लिए केले के एक छिलके को एक गिलास पानी में डालकर 10 मिनट के लिए उबालें फिर उसे ठंडा करने के बाद इसके पानी को पीने से मोतियाबिंद में राहत मिलता है।

कद्दू का छिलका बढ़ाता है इम्यूनिटी

कद्दू का छिलका कैंसर से बचाव करने में काफी हद तक मददगार है। कारण कद्दू के छिलके में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन फ्री-रेडिकल्स कैंसर से बचाव करने में सहायक होता है। इसमें मौजूद जिंक अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन सेल्स की रक्षा करने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसके लिए कद्दू का छिलका मुलायम है तो सब्जी के साथ पकाकर खायें और यदि छिलका सख्त हो गया है तो उसे छीलकर धूप में सुखाएं तत्पश्चात इसे भूनकर चिप्स के रूप में खाने से यह लाभ पहुंचाता है।

संतरे का छिलका कम करे कोलेस्ट्राल

रॉयल सोसायटी ऑफ मेडिसीन का कहना है कि संतरे या अन्य मौसमी फलों के छिलकों में सुपर-फ्लैवोलायड पाया जाता है। यह तत्व शरीर में बैड कोलेस्ट्राल को कम करने में सहायक होता है। कोलेस्ट्राल कम करने के लिए संतरे या मौसमी फलों के छिलकों का जूस बनाकर सेवन किया जा सकता है या फिर इसके छिलके को कद्दूकस करके सूप या सब्जी में मिलाकर भी इसका सेवन लाभप्रद माना जाता है।

लहसुन के छिलके से दिल रहे दुरुस्त

लहसुन का छिलका दिल को दुरुस्त रखने में रामबाण जैसा है। 'द जर्नल आफ न्यूट्रिशन' में छपे एक शोध पत्र में यह बताया गया है कि लहसुन के छिलके में फिनायलप्रोपेनायड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है। जो ब्लड प्रेशर के साथ ही साथ बैड कोलेस्ट्राल को कम करने के साथ दिल संबंधी बीमारियों से भी दूर रखता है।

दिवाली के दिन यूपीडब्ल्यूजेयू के कार्यक्रम में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने महाराष्ट्र के पत्रकारों का किया सम्मान।

विगत माह नई दिल्ली में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। यूपीआरटीयू के अध्यक्ष ने मीडिया मंच की प्रति भेंट की।

हमारे 12 खेल रत्न और 35 अर्जुन

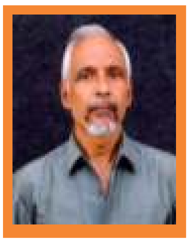

● वीरेन्द्र शुक्ल
9936403929

नेशनल स्पोर्टस अवार्ड कमेटी की अनुसंशा पर इस बार एक साथ 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के साथ ही 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है।

आमतौर पर खिलाड़ियों को बहुतायत में ये राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के आयोजन से और उसमें मिली भारत को उल्लेखनीय सफलता के चलते इतने ढेर सारे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया।

वैसे तो खेल पुरस्कार समारोह हर साल खेल दिवस यानी 29 अगस्त को किया जाता था लेकिन इस साल देरी की गई। क्योंकि सरकार खिलाड़ियों के चयन में टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी शामिल करना चाहती थी। इस कारण राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा में देरी स्वाभाविक थी। इस साल 12 के मुकाबले पिछले साल केवल चार ही खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार बांटा गया था। ये चार खिलाड़ी क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारतीय महिला हाकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक हाई जम्प के खिलाड़ी मरियप्पन थंगाबेलू थे। इस लिहाज से इस बार किसी भी एक साल में खेल रत्न के लिए सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को चुना गया है।

इस बार देर से हुई घोषणा

देरी के साथ ही साथ खेल रत्न के नाम में बदलाव भी हुआ है। पहले खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से प्रदान किए जाते थे। लेकिन अब नाम बदल कर इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम दे दिया गया है।

विश्वनाथन आनंद बने थे पहले खेल रत्न

भारत के खेल जगत में यह सर्वोच्च खेल सम्मान है। खेल में पुरस्कार की शुरुआत वैसे 1991-92 में हुई थी। पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पहला खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2020 तक 43 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका था।

खेल रत्न पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानित कर समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है। पहले पुरस्कार में खिलाड़ियों को सम्मान के रूप में एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और नगद ईनाम मिलता है। साल 2005 तक ईनाम की राशि 5 लाख रुपये थी। अब यह राशि बढ़ाकर 7 लाख 50

हजार रुपये कर दी गई है।

खेल रत्न के लिए पहले 11 खिलाड़ियों के नाम पर ही अंतिम मुहर लगी थी बाद में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह का भी नाम इसमें शामिल कर लिया गया। मनप्रीत सिंह को वस्तुतः अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश हुई थी। लेकिन बाद में उन्हें भी एक अन्य हॉकी खिलाड़ी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेस के साथ ही इस लिस्ट में जगह दे दी गई। अन्य खेल रत्न

सम्मान से विभूषित होने वाले खिलाड़ियों में भाला फेंक के ओलंपिक चैंपियन नीरज चौपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, सुनील क्षेत्री (फुटबाल), मिताली राज (क्रिकेट) के साथ ही पांच पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों प्रमोद भगत (पैरा बैडमिंटन), सुमित अंतिल (पैरा बैडमिंटन), अवनी लेखरा (पैरा शूटिंग), कृष्णा नागर (पैरा बैडमिंटन) और एम. नरवाल (पैरा शूटिंग) हैं। इस बार खेल रत्न बनने वालों में दो खिलाड़ी बेहद खास हैं। महिला क्रिकेट में मिताली राज और फुटबाल में सुनील क्षेत्री ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अपने-अपने खेलों में पहली बार खेल रत्न बनने का सम्मान मिला है।

सुहास सहित बने 35 अर्जुन

इस बार 35 अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में तीन- सुहास एल. वाई, ललित उपाध्याय और वंदना कटारिया उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।

न केवल अर्जुन पुरस्कार पाने वाले में सुहास एल. वाई पैरालंपिक खिलाड़ी हैं बल्कि इस बार अधिकांश अर्जुन बनने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी ही हैं। कारण टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत का अब तक का

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत को कुल पांच स्वर्ण, आठ रजत और छः कास्य पदक यानी कुल 19 पदक मिले हैं।

सुहास एल. वाई. न केवल बैडमिंटन के खिलाड़ी ही हैं बल्कि वह एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। आईएएस सुहास एल. वाई. इस समय गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीतने का गौरव पा रखा है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह

पहले आईएएस हैं।

ललित उपाध्याय का संबंध बनारस से हैं। भारतीय हाकी टीम के सदस्य के रूप में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इसी तरह वंदना कटारिया का संबंध भी हाकी से है। वंदना आज भारतीय महिला हाकी टीम की सर्वाधिक अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। वंदना का कर्मक्षेत्र लखनऊ रहा है। यहीं से उन्होंने हाकी की बारीकियां सीखीं।

आँखिन देखी

लोकतंत्र खतरे में है!

वीरेन्द्र सिंह
9410704385

अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन हर राजनैतिक दल को लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। जो 'लोक' से 'तंत्र' कब्जाने में फेल हो गया, वह छटपटा रहा है। लोगों के भलाई की ललक हिलोरें ले रही है। खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचने से भी नहीं चूक रहे हैं। वादों की हवा में वोटर सूखे पत्तों की तरह फड़फड़ा रहे हैं।

अल्हड़ बीकानेरी ने कहा:

'चोरों का तथा डाकुओं का राष्ट्रीकरण करवाने दो।
बस एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बना दो।।
जो बिल्कुल फक्कड़ हैं उनको राशन उधार तुलवा दूंगा।
जो लोग पियक्कड हैं उनके घर में ठेके खुलवा दूंगा।।

चुनाव महापर्व

लोकतंत्र में चुनाव महापर्व है। वोट देना जनता का महाकर्त्व्य है। यदि जनता चुनावों में हिस्सा नहीं लेती तो वह देशद्रोह कर रही है। बुनियादी सुविधाओं के अपने हक की हत्या कर रही है। जनता को अपने अधिकारों के लिए कभी भी चुनावों को ढ़ाल नहीं बनाना चाहिए। इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। वे चाहें तो नेता के सामने रोये-गिड़गिड़ायें रोड,पानी, बिजली के लिए। सुरक्षा तो कदापि न मांगे। पुलिस तो नेताओं की सुरक्षा में संगीन ताने घूम रही है। गांव-मुहल्लों में कहां से आयेगी। लोकतंत्र को संभालकर रखना नेताओं का परम कर्त्तव्य हैं। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव नियमित हों। सांसद और विधायक जीतते रहें। जीतने वाले नहीं चाहते कि कभी हारें। हारने वाले नहीं चाहते कि कोई जीते। नेता चुनाव में उतरते है तो गीता का ज्ञान धारण कर लेते है। उनके लिए साधन का नहीं साध्य का महत्व होता है। अपने सामने चाचा, ताऊ, मामा, दादा किसी को देखकर विचलित नहीं होते।

ऐन चुनाव के वक्त भी कौरव दल के सैनिक पांडव दल में जा सकते हैं। किसी परिवार का मुखिया पांडव दल में होगा तो उसके शेष सदस्य कौरव दल में। कोई इस शर्त पर विपक्षी खेमें की मदद करेगा कि उसे हथियार उठाने के लिए न कहा जाये अर्थात उसका नाम उजागर नहीं होगा। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है । इसमें चुने गये भगवान रहते हैं। भगवान के आपस में लड़ने, जूत्तम-पैजार करने या संसद की कारवाई बाधित करने से लोकतंत्र पुष्पित-पल्लवित होता है। नेता के पास चुनावों का गणित होता है। राजपूत अमुक संसदीय क्षेत्र में बीस प्रतिशत हैं। बाभन हैं पंद्रह प्रतिशत, अन्य जातियों की संख्या अधिक है, लगभग चालीस प्रतिशत तो वही हैं। टिकट का बंटवारा इसी गणित के आधार पर होता है। अब तो सभी जातियों के ठेकेदार भी पैदा हो गए।

राजनीतिक लोकतंत्र

हमने राजनीति शास्त्र के एक मर्मज्ञ ने पूछा, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है?

जवाब मिला आजादी, समानता और भाईचारा। लोकतंत्र की इस परिभाषा में दम नजर आया। सच में आजादी का मतलब कुछ भी करने की छूट यानी रामनाम की लूट। इसमें गधे और घास दोनों को बराबर छूट की है। घास आजाद है कि चाहे जितनी बढ़े। गधे स्वतंत्र हैं कि

लेटे-लेटे या खड़े-खड़े कुछ भी करें, जितना चाहें इस घास को चरें। कोई रोक-टोक नहीं है। लोकतंत्र में समानता भी होती है।

यह समानता सभी वर्गों, क्षेत्रों में दिखती है। यदि नहीं है तो उसकी जद्दोजहद बदस्तूर जारी है। गरीबों और गरीबों में समानता है। अमीरों और अमीरों में समानता है। मंत्रियों और मंत्रियों में समानता है। संत्रियों और संत्रियों में समानता है। चोरी, डकैती, सेंधमारी, बदमाशी, राहजनी, आगजनी, घूसखोरी, जेबकतरी इन सबमें समानता है। असमानता तो कहीं दिखती नहीं।

समाज में भाईचारा भी कायम है। हर नेता एक-दूसरे के आगे चारा डालकर भाईचारा बढ़ा रहा है। जिसके पास डालने को चारा नहीं है, उसका किसी से भाईचारा भी नहीं है। दुर्भाग्य से अगर वो बेचारा है, तो इसका हमारे पास कोई चारा नहीं है।

हमारे यहाँ राजधानी से लेकर गाँव की पगडंडी तक लोकतंत्र पसरा हुआ है। परंतु कई सालों से वही-वही चेहरे शिखर पर दिखाई दे रहे हैं। न चेहरा बदला और न चरित्र। हां, समय की मांग के साथ चालबाजी जरूर बदल गई।

एक चौराहे पर कुछ युवा जमा थे। पूंछने पर बोले कि हमें निर्देश मिला है कि कल अमुक पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना है। बताया गया है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमें उसे बचाना है। क्या खतरा है? ये सब हम नहीं जानते। हमें तो बस लोकतंत्र को बचाना है, कल जंगी प्रदर्शन करके।

अब तो हम कह सकते हैं, हमारा लोकतंत्र बहुत महान है। यह गौरव की बात है कि हमारे मुल्क में अभी भी 35 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं।

वे कहाँ अंगूठा लगाते हैं, उन्हें पता नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि विचार न जन्मे, सोच पैदा न हो और लोकमत सदा दिग्भ्रमित रहे। लोक कहीं भी जाए, परंतु तंत्र सदा हमारे हाथ में रहे।

पार्टी हाईकमान

हर राजनीतिक दल में पार्टी का एक हाईकमान होता है, जो कभी नहीं चुना जाता। वह सिर्फ होता है, ब्रह्म की तरह सर्वशक्तिमान। वह कहाँ से आता है और किस प्रकार हाईकमान कहलाने लगता है, यह कोई नहीं जानता। परंतु शक्ति उसकी असीम है। वह सरकार और पार्टी में राई को पर्वत और पर्वत को राई आसानी से बना सकता है। एक दफे जो व्यक्ति, जिस पार्टी में हाईकमान हो गया से हो गया। फिर उसका पाँव अंगद का पाँव, जिसे उठाना तो दूर कोई माई का लाल हिला तक नहीं सकता। यह हाईकमान का लोकतंत्र है, जिसमें लोक भी वही है और तंत्र भी वही। एक कार्य समिति का लोकतंत्र होता है। यह लोकतंत्र भी रहस्यवाद की तरह पूरी पार्टी में व्याप्त रहता है। इसकी थाह विरले ही पा पाते हैं। यों किसी भी पार्टी की कार्य समिति हाईकमान के प्रभा मंडल से कभी मुक्त नहीं होती। उसे मुक्त होना भी नहीं चाहिए, अन्यथा उसके सदस्यों का जीवन असुरक्षित हो जाएगा। वैसे, कागज पर लोकतांत्रिक परंपराओं का पूर्ण पालन होता है। प्रस्ताव आते हैं। उन पर बहसें होती हैं। लोग टीका-टिप्पणी करते हैं। परंतु होता वही है, जो मंजूरे हाईकमान होता है।

यही सार्थक और मूल्यवान लोकतांत्रिक आदर्श है। वैसे, कार्य समिति, उच्च अधिकार समिति और ऐसी ही बड़ी-बड़ी समितियों को देखकर लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। जड़ें सचमुच गहरी और मजबूत भी हैं। इसलिए व्यक्ति पूजा की, उपासना की, पुरातन पद्धति आजकल लोकतंत्र के दायरे में लाई जा रही हैं। अब लोग फख्र से कहते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी में गुटबाजी है। जैसे गुटबाजी परम गौरव की बात है। गुटबाजी जब गौरव है तो भितरघात उपलब्धि है। गुटबाजी को आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया तो भितरघात के लिए इतनी हाय-तौबा क्यों? कहते हैं कि वैचारिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की जान है।

हमारे यहाँ गुटीय स्वतंत्रता लोकतंत्र की जान है। एक-एक पार्टी में कई-कई गुट हैं। इस परंपरा पर हमें गर्व है। हर गुट का अपना संविधान है। अपना लोकतंत्र है। बावजूद वे एक हैं। अनेकता में एकता। आए दिन सभी गुट मिलजुल कर घोषणा करते हैं कि हममें कोई गुटबाजी नहीं है। परंतु मंच से उतरते ही सबकी डफली के अलग-अलग राग सुनाई देने लगते हैं। हमारे लोकतंत्र की यह स्वस्थ परंपरा है।

जब गुट हैं तो कहीं भूल से आप यह न समझ लें कि समान विचारधारा वालों का कोई वर्ग होगा। भारतीय राजनीति की यही तो विशेषता है कि यहाँ विचार से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। विचार वाले लोग तो यहाँ नेपथ्य में शोभा देते हैं। गुट के केंद्र में सदा से 'विचार' नहीं 'प्रभाव' रहा है। जो प्रभावी है, वही मुखिया है। जो चुनाव में टिकट दिला दे। जो मंत्री बनवा सके। लफड़ों में फँस जाने पर जो बेदाग बरी करा दे। जिसके पास धन हो। बल हो। छल हो। और दस-बीस स्थानीय समर्थक हों। जो हर हालत में रात को दिन और दिन को रात सिद्ध करता रहे। ये सब बातें एक साथ जिसमें हो, वह परम प्रतिभाशाली है। लोकतंत्र का रत्न है। वह जो कहे, वह लोक की आवाज है। वह जो सोचे, वह समाज की सोच है। वह जो करे, वह देश का कृत्य है। इस प्रकार गुटबाजी का अपना लोकतंत्र अति महत्वपूर्ण है। अलग-अलग गुट जब एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो सार्वजनिक रूप से यह लोकप्रिय वक्तव्य जरूर देते हैं- 'लोकतंत्र खतरे में है।'

लोक भेद

हमारे यहाँ लोकतंत्र में लोक में भेद डालकर जातियों में बांट दिया जाता है। लोक की कोई आवाज नहीं होती। पिछड़ी जाति की गुहार, अगड़ी जाति की अपील, महिलाओं की चीख, गरीबों की चीत्कार, बच्चों का रुदन, बूढ़ों की कराह, युवाओं की हाय! अमीरों की वाह! सब मिलाकर ऐसा कोरस बजता रहता है कि समझ में ही नहीं आता कि लोकमंशा क्या है? हमारे लोकतंत्र में यह एक सफल प्रयोग है कि चीजों को इतना उलझा दो कि वे कभी भी न सुलझें। किसी कवि ने लिखा है-

प्रजातंत्र करता रहा, नित नित नए प्रयोग।
जिसने चाहा कर लिया, अपने हित उपयोग।।

जब राजधानी में कई प्रयोग हो चुके तो लोगों ने सोचा, चलो, ग्राम स्तर पर भी कुछ प्रयोग किए जाएँ। गाँव वालों को जबरदस्ती जोड़ा गया। वे रात-दिन मेहनत-मजूरी में लगे रहते, तब कहीं जाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाते। उन्हें समझाया गया, परिवार को पालने के और भी कई तरीके हैं। नई तकनीक निकल आई हैं। देखो, शहर में कार्यकर्ता होते हैं। कभी देखा है उन्हें? ज्यादा खाते हैं, कम काम करते हैं और सदा खुश रहते हैं। हमें ऐसे हँसते, खेलते, मुस्कराते लोग गाँव में चाहिए। प्रशिक्षण चालू है, चलो भर्ती हो जाओ। तुम्हारी आवाज ऊपर तक पहुँचेगी। यह आदर्श है। फिलहाल हमें ऊपर की आवाज बिल्कुल नीचे तक पहुँचानी है। हमें किसी भी तरह विचार को वोट में बदलना है। बड़ा कंपटीशन है इस क्षेत्र में।

सोच-विचार में समय की बरबादी होती है। कैसे भी कोई एक छाप हमें आदमी के दिमाग में टाँक देनी है। मोहित कर देना है सबको उस छाप से। लोगों को इस छाप के अलावा संपूर्ण संसार शून्य दिखाई दे, तो समझो हमारा लोकतंत्र सफल है। गाँव-गाँव में प्रयोग चल रहा है। पहले गाँव में एक मुखिया होता था। कभी कोई समस्या आ जाए, तो पाँच बड़े बुजुर्ग लोग 'पंच परमेश्वर' हो जाते थे। अब छोटे-छोटे गाँवों में बड़े-बड़े झंडे हैं। 'पंच परमेश्वर' तो अब कहीं ढूँढ़े नहीं मिलते। हाँ, कार्यकर्ता, भैये, छुटभैये, नेता, अभिनेता, पंच, सरपंच, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, मीटिंग, मेमो, निर्देश, शिकायत, घपला, ठेका, जाति, पार्टी, झंडा, प्रचार, पर्चा, बूथ, पुलिस, गोली, हत्या और चालान- ये शब्द गाँवों की हवा में तैरने लगे हैं। हमें खुशी है लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुईं। राजधानी के खेल हमने गाँव की चौपाल तक पहुँचा दिए।

लोकतंत्र भीड़तंत्र में तब्दील हो गई। जिसके साथ भेड़ों का बड़ा झुंड वह झंडावरदार हो गया। जमातों में बंट गई जम्हूरियत। सिद्धांत, नीतियां, मर्यादाएं दफ्न हो गईं। उग आए नफरत, फिरकापरस्ती, मौकापरस्ती के कंटीले कैक्टस। बेढब बनारसी की बेबसी:

'बैण्ड सरकार के चाहे कोई बजा ले,
कुरसी का शासन के कोई भी मजा ले।
पेट नहीं भरता है जब तक हमारा,
कोई नहीं अच्छा हमें लगता है नारा।'

खादी फैशन में ऋतु का जलवा

अंजलि त्रिपाठी
9935280120

लखनऊ में खादी के संग, फेशन के रंग की जो युगलबंदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी महोत्सव में हुई वह बेमिसाल थी। गांधी की खादी आधुनिकता के रंग में पूरी तरह रंगी नजर आई। देश के नामचीन फैशन डिजाइनरों के कलेक्शन को अपने शरीर पर धारण कर जिस तरह मॉडलों ने रैंप पर वॉक किया वह सब देखकर दर्शक दंग रह गए।

मार्क्स आडिटोरियम में जब फेशन का ये जलवा.... नशा ही नशा है, मजा ही मजा है..... जैसे गीतों पर मॉडल्स ने रैंप वॉक के साथ फेशन शो का आगाज किया तो सभी मंत्रमुग्ध हो उठे। इस खादी महोत्सव में खादी को केवल फैशन से ही जोड़ने का काम नहीं हुआ बल्कि आम परिधान के रूप में जन-जन से जोड़ने का भी काम हुआ। वैसे डिजाइनरों ने खादी के कई आधुनिक परिधान मंच पर पेश किए लेकिन उसमें ढेर सारी वैरायटी से हर कोई खादी से जुड़ने को उत्सुक नजर आया। इसी का नतीजा था कि शादी में खादी कलेक्शन को देखकर लोगों ने भरपूर सराहा। फैशन शो की शुरूआत जानी मानी फेशन डिजाइनर फराह अंसारी द्वारा तैयार परिधानों के प्रदर्शन से हुई।

वैसे तो 20 महिला मॉडलों ने रैंप पर अपने जलवे से छटा बिखेरी लेकिन उसमें मिसेज इंडिया रह चुकीं ऋतु सुहास का अंदाज सबसे

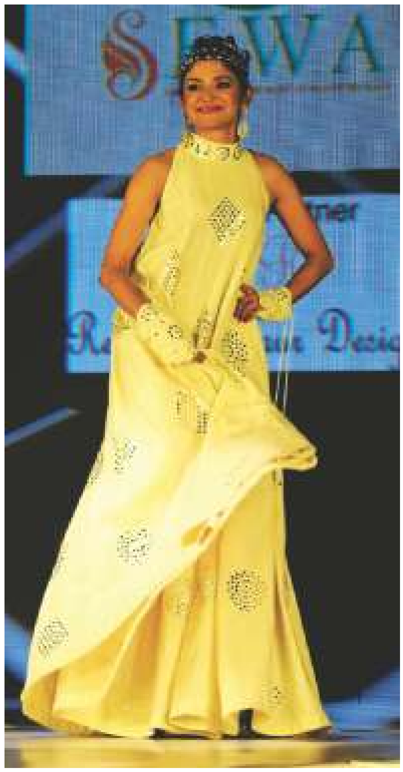

जुदा और मनमोहक नजर आया।

उल्लेखनीय है कि ऋतु सुहास का जलवा 2019 में न केवल मिसेज इंडिया के रूप में ही नजर आया बल्कि वह एक कुशल और सक्षम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। बतौर पीसीएस अधिकारी ऋतु गाजियाबाद में एडीएम हैं। जबकि उनके आईएएस पति सुहास एल. वाई. गौतमबुद्ध नगर के डीएम हैं। अपनी पत्नी की ही तरह सुहास विविध व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वह पैरालंपिक में टोक्यो में अपने प्रिय खेल बैडमिंटन में रजत पदक तक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं।

उत्तर प्रदेश खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित इस फैशन शो में जानी-मानी फैशन डिजाइनर रीना ढाका, फैशन डिजाइनर रितु बेरी, फेशन डिजाइनर हिम्मत सिंह और फैशन डिजाइनर असमां हुसैन के कलेक्शन देखने को मिले। इसमें खादी की साड़ी, लहंगा-चोली, शरारा, इंडोवेस्टर्न फ्यूजन, लांग स्कर्ट्स और मिनी डिजाइनर टॉप, धोती-कुर्ता और शेरवानी समेत कई तरह के लुभावने परिधानों को लोगों ने देखा।

इस कलेक्शन में तीन तरह के संग्रह शामिल थे। पहले संग्रह में खादी कपास में आठ लहंगों का एक समूह था जिसमें चिकनकारी और गोटा-पट्टी के साथ कढ़ाई की गई थी। दूसरे संग्रह में खादी शिल्प का लहंगा, गरारे, फर्शी जैकेट, स्कर्ट और ट्राउजर था। इस संग्रह के अंतर्गत दुल्हनों के लिए फर्शी और दूल्हों के लिए शेरवारी और बंद गले के परिधान इस कलेक्शन का हिस्सा था। सिल्क फैब्रिक को टुकड़ी के काम से तैयार किया गया था जो लखनऊ का एक उत्कृष्ठ हस्तशिल्प है। इसमें ऊपर भारी गोल्ड जरदोजी की कढ़ाई की गई थी। ये वस्त्र शादी और वलीमे के वक्त काम आते हैं।

तीसरा संग्रह दूल्हा और दुल्हन का लाल संग्रह रहा। जिसमें करारा, लहंगा, दुल्हन के लिए फर्शी और दूल्हे के लिए सुनहरी शेरवानी थी। इन कपड़ों को मेटेलिक जरदोजी की कढ़ाई से सजाया गया था।

खादी व हैंडलूम पर विशेष काम के लिए पहचानी जाने वाली जयपुर की फराह अंसारी के परिधानों पर रीना राठौर द्वारा तैयार आभूषणों को पहनकर जब शो स्टापर ऋतु सुहास रैंप पर आईं तो जोर तालियों से दर्शकों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा इसी के साथ जब दोबारा राजधानी की फेशन डिजाइनर अदिति जग्गी रस्तोगी के बकरम और खादी को मिलाकर एकदम यूनिक ड्रेस के कलेक्शन को धारण कर जब ऋतु सुहास रैंप पर उतरी तो शायोनारा कहती आशा पारिक का प्यारा अंदाज लोगों के जेहन में कौंध गया। इसके अलावा ऋतु सुहास ने असमां हुसैन के शादी में खादी कलेक्शन से जुड़े परिधान को पहनकर रैंप पर उतरीं तो यह नजारा भी बेहद दिलकश था। इसके अलावा सुपर मॉडल दिव्या खासलेवाल सहित अन्य मॉडलों ने भी शादी में खादी कलेक्शन को लेकर रैंप पर इठलाती हुई आईं तो माहौल बेहद खुशनुमा नजर आया।

ऋतु सुहास के अलावा मिस इंडिया रनर अप रह चुकीं पंखुडी गिडवानी और सुपर मॉडल आकांक्षा ने भी अपनी अदाओं और परिधानों को मोहित कर दिया।

इस अवसर पर विशिष्ट लोगों में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, मुख्य सचिव आर. के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल आदि मौजूद थे।

आलिया की कमाई पिता महेश भट्ट से ज्यादा

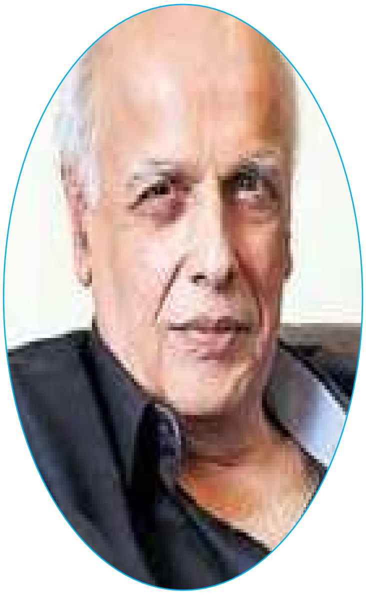

फिल्मकार महेश भट्ट अपने बेटी आलिया भट्ट के बारे में आज दिल खोलकर प्रशंसा करने से नहीं चूकते हैं।

उल्लेखनीय है कि आलिया भट्ट ने सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बालीवुड में एंट्री की थी और आज वह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय और प्रतिभा संपन्न एक्ट्रेस मानी जाती हैं। इस बारे में महेश भट्ट का कहना है कि उनकी बेटी आलिया केवल अपने पैरेंट्स के नक्शे कदम पर नहीं चलती है बल्कि उसके अंदर अपनी ही एक आग है। हालांकि मैं भी एक फिल्मकार था मगर मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाकर रखता था। मैं अपनी रोजी-रोटी के लिए फिल्में बनाता था और यही बात शायद आलिया के दिमाग में घर कर गई है। वह पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करती है।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले तक आलिया एक छोटी बच्ची थी जो पांच सौ रूपये के लिए अपने पिता की ख़ुशामद करती थी और अब दो साल के भीतर ही उसने इतना पैसा कमा लिया है जितना मैं 50 सालों में भी फिल्में बनाकर नहीं कमा पाया। स्टूडेंट आफ इ ईयर से डेब्यू करने के बाद आलिया ने हाई-वे, टू स्टेटस, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, राजी, गली ब्वाय, कलंक और सड़क-2, जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। जिनमें उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई है।

विक्की ने जीता कैटरीना का दिल, अब होगी शादी

बालीवुड की फिजाओं में इस समय अभिनेता विक्की कौशल और फिल्मी एक्ट्रेस एवं ख़ूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ की शादी की चर्चा जोरों पर है साथ ही जिस ढंग से विक्की ने कैटरीना को प्रपोज किया उसका किस्सा भी लोगों को खूब लुभा रहा है।

हाल ही में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बीच चलने वाले अफेयर और शादी को लेकर कई तरह की ख़बरें सामने आई हैं। विक्की ने बड़े रोमांटिक अंदाज में अपने दिल की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने कैट की फेवरेट डार्क ब्राउनी चॉकलेट बनवाई और उसे लेकर कैट के घर जा पहुंचे। जब कैट ने डिब्बे को खोला तो उसमें उन्होंने एक नोट और रिंग पाया। नोट पर लिखा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस सरप्राइज पैकेज को लेकर कैट इतनी भाव-विभोर हो गईं कि उन्होंने हां कर दी।

अब दोनों दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों ने मिलकर शादी के बाद रहने के लिए एक घर भी फाइनल कर लिया है। जिसमें दोनों अपनी गृहस्थी बसायेंगे। इस घर के लिए दोनों ने मिलकर बहुत पैसे खर्च किए हैं।

जातियों और मूर्तियों के सहारे यूपी की जंग जीतने उतरे दल

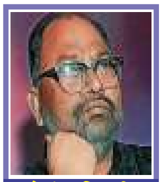

हेमंत तिवारी
मो.-9889433333

उत्तर प्रदेश में इन दिनों जातियों और मूर्तियों को लेकर घमासान मचा है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें करीब आ रही हैं, जंग तेज हो रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रमुख विपक्षी दल इस जंग के अहम किरदार हैं। दोनो दलों के जातीय सम्मेलन धुंआधार तरीके से हो रहे हैं, बांहे चढ़ाई जा रहीं और खुद को जाति का असली सेवक व हितैषी बताया जा रहा है। दूसरी ओर मूर्तियों की सियासत भी जातियों को तुष्ट करने के लिए तेज हुयी है।

सबसे पहले बात मूर्तियों की करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मूर्तियों की सियासत तेज हो गई है। इन मूर्तियों का सीधा कनेक्शन जातीय राजनीति से है, इसलिए राजनीतिक दल इन्हें लगा भी रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जहां भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, वहीं निषाद वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है।

बीजेपी नेताओं ने परशुराम की 16 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है और यह प्रयागराज में लगने जा रही है। चुनावी अखाड़े में बीजेपी से दो-दो हाथ कर रही एसपी ने लखनऊ के जनेश्वर पार्क में परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का एलान किया है। यह प्रतिमा जयपुर में तैयार की जा रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कभी भी इस प्रतिमा को लगाया जा सकता है।

बीएसपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी है। 2007 में उसे इस दांव का फायदा मिला था और प्रदेश में पहली बार उसने अपने दम पर सरकार बनाई थी। पूर्वांचल में निषाद मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है और इन्हें अपने पाले में लाने के लिए ही बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है।

गोरखपुर में निषाद मतदाताओं की तादाद 15 फीसदी से ज्यादा है। इसके अलावा महाराजगंज, जौनपुर और पूर्वांचल के कुछ और इलाकों में भी निषाद वोटरों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल में इस समुदाय की आबादी 14 फीसदी तक मानी जाती है।

मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में कुर्मी, कोइरी, राजभर, प्रजापति, पाल, अर्कवंशी, चौहान, बिंद, निषाद, लोहार जातियां सत्ता की चाभी की भूमिका में नजर आएंगी। इनकी महत्ता को भांपते हुए सभी प्रमुख दल इन जातियों को साधने में जुटे हैं। लगभग 32 फीसदी वोट का मालिकाना हक रखने वाली इन जातियों को साधने की रेस में भाजपा और सपा अन्य दलों से आगे हैं। भाजपा इनकी ताकत को अपने से जोड़े रखने की मुहिम में है जबकि सपा इन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश में जुटी है।

वैसे ये जातियां हैं जो किसी एक दल से बंधकर नहीं रही हैं। चुनाव दर चुनाव इनकी पसंद बदलती रही है। इनकी गोलबंदी चुनाव में जिसकी तरफ होती है वह सत्ता में आते हैं। यही कारण है कि इनके क्षत्रपों और राजनीतिक दलों को साधने की सीधी होड़ भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे बड़े दलों में लगी है।

देखा जाए तो वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव से कुर्मी, कोइरी, राजभर, प्रजापति, लोहार, निषाद आदि जातियां भाजपा के साथ गोलबंद हुई थीं। फिर वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में भी ये जातियां भाजपा के साथ थीं, जिसकी बदौलत भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इन जातियों के खिसकने से ही पहले बसपा और फिर सपा का राज्य की सत्ता से सफाया हुआ था। मझवारा बिरादरी को साथ जोड़ने में जुटे डा. संजय निषाद अभी तक तो भाजपा के साथ खड़े हैं। कुर्मी वोटों की राजनीति करने वाली केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (एस) भी भाजपा के साथ हैं।

2019 लोकसभा चुनाव में राजभर बिरादरी का वोट कुछ हद तक भाजपा से कटा था। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशी उतार कर इस बिरादरी के वोट को अपने पक्ष में किया था। राजभर के गठबंधन के साथ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी का साथ काफी समय से हैं और दोनो के सपा के साथ जाने पर कुशवाहा बिरादरी भी कुछ हद तक उसके पक्ष में जा सकती हैं। राजभर अब सपा के साथ खड़ें हैं और प्रदेश भर में घूम घूम कर भाजपा का सफाया करने की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले राजभर ने 10 छोटे दलों को जोड़ कर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था और आज की तारीख में इस गठबंधन के ज्यादातर दल सपा के साथ हैं या जाने को तैयार हैं।

ओबीसी में ही शामिल बंजारा, बारी, बियार, नट, कुजड़ा, नायक, कहार, गोंड, सविता, धीवर, आरख जैसी बहुत कम आबादी वाली जातियों की गोलबंदी भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी। यह वह जातियां हैं जिन्हें पिछड़ों में कुछ बड़ी आबादी वाली जातियां अपनी उपजातियां भी बताती हैं। इनकी आबादी आधा फीसदी से लेकर डेढ़ फीसदी के बीच है।

गौरतलब है कि वर्ष 2007 में जब मायावती सत्ता में आईं। उस चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर, सुखदेव राजभर के साथ ही पटेल, चौहान आदि बिरादरियों के तमाम मजबूत नेता उनके साथ थे। ब्राम्हण व क्षत्रित समाज के भी तमाम बड़े नेता उस समय बसपा के साथ में थे। वहीं जब सपा वर्ष 2012 में अखिलेश जब सत्ता में आए उस समय उनके साथ भी इन बिरादरियों के तमाम बड़े नेता जुड़े थे। पटेल, चौहान, कुशवाहा आदि बिरादरियों के बड़े नेता सपा के साथ खड़े हो गए थे।

आज की हालात तो ये है कि सपा-भाजपा में से कोई भी दल यह बात पक्के तौर पर नहीं कह सकता है कि पिछड़ी जातियों का एकमुश्त वोट उसे मिलने जा रहा है। पिछड़ी जातियां अभी खुद अपना समर्थक दल नहीं तय कर सकी हैं हां कुछ के नेताओं ने जरुर पाला चुन लिया है। पिछड़ों के इस असमंजस को भांपते हुए दलों में उनको लुभाने की कवायद तेज हो गयी जो आने वाले कुछ महीनों तक जारी रहेगी।

hemant.jansandesh@gmail.com

2.61 करोड़ परिवारों को शौचालय

10 करोड़ लोग लाभान्वित

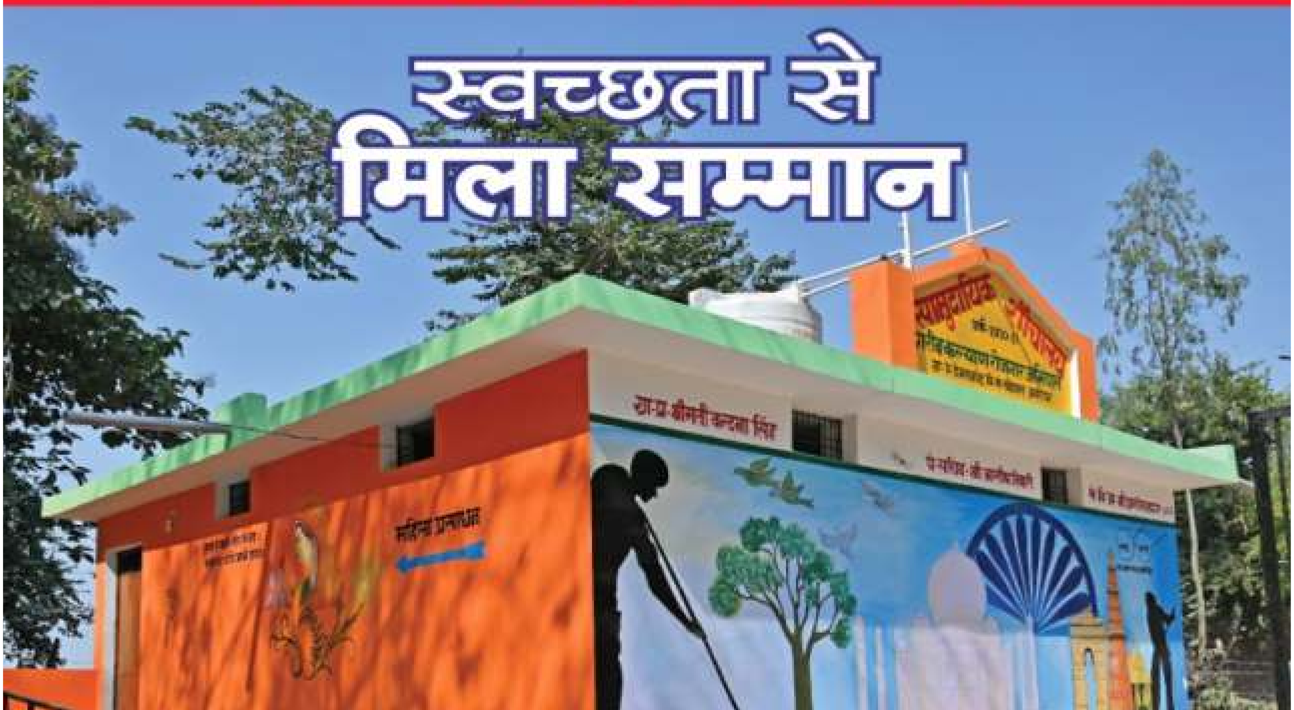

सोच ईमानदार, काम दमदार

Published on 10th & Posted on 15th, 17th & 19th of every month at RMS Lucknow. Total number of pages 52.
RNI No. UPHIN/1998/5628 Postal Regd. No. GPOLW/NP-90/2021-23